RNI No. : CHHHIN/2011/40280

पाक्षिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ आजतक

वर्ष : 11 • अंक : 09 • जनवरी - प्रथम 2022 • मूल्य : 30/-

नीरज पाल
महापौर, भिलाई

निर्मल कोसरे
महापौर, भिलाई चरोदा

नंदलाल देवांगन
महापौर, बीरगांव

शशि सिन्हा
महापौर, रिसाली

जय-जयकार नगर सरकार

सोशल इंजीनियरिंग से जीता मैच

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग से जीत हासिल कर यह संकेत दे दिया है कि जनता का समर्थन अभी भी सरकार के साथ है.

टूट गए सारे मिथक, जनता जनार्दन का राज तिलक

हमर रिसाली - नवा रिसाली - गढ़त रिसाली - बढ़त रिसाली
गढ़बो नवा रिसाली
श्री भूपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन
केशव बंछोर
सभापति, रिसाली नगर निगम
जितेन्द्र साहू
महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी
श्री ताम्रध्वज साहू जी
केबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
रिसाली नगर निगम के
प्रथम महापौर, सभापति
एवं समस्त पार्षदगणों को
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
शशि सिन्हा
महापौर, रिसाली नगर निगम
जय छत्तीसगढ़ ... गढ़बो नवा रिसाली... गढ़बो नवा छत्तीसगढ़
विनीत : रिसाली नगर निगम क्षेत्र के समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण
संपूर्ण भारत वर्ष में सबसे तेज गति से जनहित का काम करने वाली सरकार - भूपेश बघेल सरकार - कांग्रेस पार्टी की सरकार

E-Mail : cg.aajtak@gmail.com

04

जी.पी. सिंह आखिरकार गिरफ्तार

17

जय-जयकार नगर सरकार

प्रदेश के हाईप्रोफाइल दुर्ग जिले के तीन बड़े निकायों के चुनावों में कांग्रेस ने परचम फहराकर.....

लाभ की खेती मखाना

कोरोनाकाल में जहां लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है. लोग भयभीत और डरे हुए हैं. इसी भय की वजह से कई लोगों की मौतें भी हुई हैं. ऐसे समय में रोग प्रतिरोधक...

26

30

छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम

जामतारा के बाद छत्तीसगढ़ साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है. प्रदेश पुलिस के साथ नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने भी इस बात..

कवर्धा की फिजां में साम्प्रदायिक जहर

भोरमदेव की ऐतिहासिक नगरी कवर्धा का सामाजिक ताानाबाना तार-तार हो रहा है. अक्तूबर 2021 के प्रथम सप्ताह में यहां हुए झंडा विवाद को केन्द्रित कर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें अब अपने चरम पर हैं. पूर्व मुख्यमंत्री के गृह नगर की फिजां में घुला यह जहर अब पार्टी स्तर से ऊपर उठ गया है. कांग्रेस के प्रभावशाली हिन्दू नेताओं....

08

गुंडाधुर के पड़पोते ने किया मतांतरण

बस्तर का विशाल आदिवासी समाज जो क्रांतिवीर शहीद गुंडाधुर को अपना आदर्श मानते हैं और जल- जंगल- जमीन के लिए लड़ना सिखाने...

38

10

राजभवन की कार्यशैली पर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षाविदों की कमी नहीं है. इसके बावजूद क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में बाहर के लोगों को कुलपति पद पर क्यों बिठाया जा रहा है. यह सवाल अब गहराता जा रहा है. राज्यपाल एक विशेष विचारधारा के लोगों को कुलपति बनाना चाहती है. यह विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस महत्वपूर्ण पद पर एक विचारधारा.....

44

अंगदान महादान...

किसी व्यक्ति के जीवन में अंगदान के महत्व को समझने के साथ ही अंगदान करने के लिए आम इंसान को प्रोत्साहित करने 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने की उपयोगिता अंगों की अनुपलब्धता के कारण बढ़ती जा रही है. वैसे भारत में प्रतिवर्ष 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया..

संपादकीय, विज्ञापन, प्रसार कार्यालय
ब्लॉक बी-1, प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.)
492001 फोन : 0771-4221384

संपादक लखन लाल | **सलाहकार संपादक** सादात अनवर | **विशेष प्रतिनिधि** मंजुला कौशिक | विक्रम जनबंधु, विजय प्रताप कश्यप | **कानूनी सलाहकार** गिरीशचंद्र शर्मा

प्रतिनिधि : •**रायपुर**-भूपेन्द्र वर्मा •**दुर्ग**-रामशरण कौशिक •**पाटन**-महेश शर्मा •**भिलाई**-श्यामलाल साहू •**भिलाई-3**-सतीशदास वैष्णव •**राजिम**-राजेन्द्र भारती •**राजनांदगांव**-राहुल गौतम •**कबीरधाम**-सुरेश प्रसाद गुप्ता •**कोरबा**-गेंदलाल शुक्ला •**जांजगीर चांपा**-समयदास अविनाशी •**कटघोरा**-विकास जायसवाल •**कोण्डागांव**-सुरेश पाटले •**नारायणपुर**-नरेन्द्र देवांगन •**जगदलपुर**-हेमंत कश्यप •**धमतरी**-जियाऊल हुसैनी •**बलौदाबाजार**-संतोष यादव •**तिल्दा नेवरा**-दिलीप वर्मा •**बोड़ला**-नवलकिशोर श्रीवास्तव •**बिलासपुर**-राजन कुमार सोनी •**धरसींवा**-देवेन्द्र वर्मा •**अंबिकापुर**-धनंजय दुबे •**मनेन्द्रगढ़**-मनप्रीत सिंह साहनी •**रामानुजगंज**-विकास केसरी •**वाड्रफनगर**-नितेश श्रीवास्तव •**दल्लीराजहरा**-झुनमुन गुप्ता •**गुण्डरदेही**-रमेश चांडक

सरगुजा प्रभारी अमरेश्वर दुबे
मार्केटिंग एवं फोटो जर्नलिस्ट पी. मोहन

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- लखन लाल के लिए सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ब्लॉक बी-1 प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित, **संपादक - लखन लाल**

सर्वाधिक सुरक्षित : किसी भी रूप से सामग्री की नकल प्रतिबंधित है. सभी विवादों का निपटारा रायपुर न्यायालय में होगा.

लखन लाल

संपादकीय

काहे का बाबा, काहे का संत

शांति के टापू छत्तीसगढ़ में कालीचरण ने सियासी उबाल ला दिया है. आखिर बेहद ठंड के इस मौसम में ये राजनीति की गर्म हवाएं कहां से आ रही है, इनको पहचानना भी जरूरी है और इन्हें ढूंढना भी. पहले भी राज्य में हिन्दू-मुस्लिम दंगा भड़काने की कथित कोशिश कवर्धा में की गई और अनेक हिन्दू संतों के आगमन ने वहां गर्म अलाव की भट्टियां सुलगा दी. वो तो प्रदेश सरकार की सदैव सचेत रहने, राज्य की सुरक्षा और बाहरी तत्वों के प्रदेश में घुस आने के कथित मंसूबों को ध्वस्त करने की मुहिम के चलते षड्यंत्रकारियों की चालें विफल होती रहीं. यह समझने की जरूरत है कि राज्य में ऐसे मुसलमान कहां हैं जो वर्षों की शांति व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर अमन पसंद प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं. जाहिर है कि इसे आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद और धर्म संसद ही बेहतर बता पाएं जिन्हें अपने आयोजनों में हिन्दू-मुस्लिम दंगा फैलने का डर सता रहा है.

क्या वजह है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरे राज्यों में चुनावी मोर्चा संभालते हैं तब ही छत्तीसगढ़ में बड़ी वारदात हो जाती है. कहीं यह षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है? चाहे वह बस्तर के "तर्रेम" में नक्सली हिंसा में 22 जवानों के शहीद होने की घटना हो या कवर्धा में साम्प्रदायिक उन्माद का मामला. इन दोनों घटनाओं के समय में पहले वे असम में चुनावी मोर्चा संभाले हुए थे, दूसरे के समय में वे यूपी चुनाव में व्यस्त थे. यूपी में भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग को साधने में लगे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही छत्तीसगढ़ की शांति को भंग कर यहां यूपी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिशें आरंभ हो चुकी हैं. भूपेश ने कालीचरण पर तंज भी कसा है कि वो कालीचरण है या गालीचरण. क्या उसे गाली देने के लिए भेजा गया था. इसके पीछे क्या उद्देश्य है, हम लोगों को नहीं पता. इससे पहले छत्तीसगढ़ में उन्हें नहीं देखा गया, लेकिन अचानक वे प्रकट हुए और महात्मा गांधी के खिलाफ अनर्गल बातें और हत्यारे गोडसे की प्रशंसा करने लगे. महात्मा गांधी हमारे अभिमान हैं और उनके बारे में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है.

पुलिस के सामने भी उसने कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं. उसे अपनी कही गई बातों का कोई पश्चाताप नहीं है. जाहिर है कि अपनी बातों से घृणा और हिंसा फैलाने से बढ़कर अधर्म नहीं है. जब विदेश में गांधी पर फिल्में बनकर प्रशंसा पा रही हों, आज भी उन पर शोध हो रहे हों ऐसे में अपने ही देश के किसी व्यक्ति ने उठकर रायपुर की धर्म संसद में गांधी के बारे में आपत्तिजनक वाक्य कहे. उस साधु ने साधुत्व की सारी हदें पार कर दीं. इन घृणित विचारों का उस समारोह में कुछ साधु-संतों ने विरोध भी किया, लेकिन अपने आपको संत कहलवाने वाले को तार-तार कर दिया. कुछ लोग साधु-संत के वस्त्र तो धारण कर लेते हैं लेकिन उनके बोल और व्यवहार साधुत्व की मर्यादा का पालन नहीं कर पाते हैं.

साधु का सही अर्थ तो उसे गाली देने के परिप्रेक्ष्य में क्षमादान करने का होता है, लेकिन यह कालीचरण किस मानसिकता का है जो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करता है. जिस तरह से कालीचरण ने गांधी को गाली दी उससे सवाल पैदा होता है कि क्या देश का आम हिन्दू समुदाय भी उसका समर्थन करता है. जाहिर है कि गोडसे को पूजने वाले कई लोग इस देश में है, लेकिन वह खुलकर सामने नहीं आते. उन्हें डर है कि ऐसा करने से वे देशद्रोही कहलाएंगे जैसा कि कालीचरण के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने किया. ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है. वे छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों में भय और साम्प्रदायिकता का संचार होते नहीं देखना चाहते.

छत्तीसगढ़ को "धान का कटोरा" कहा जाता है. यह धरती किसानों की है. यहां का हर कमाऊपूत अपनी रोजी-रोटी को लेकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है. राज्य की आम जनता के जेहन में कभी हिन्दू मुस्लिम जैसा कोई भाव नहीं आया. गांव हो या शहर सब जगह आपसी सद्भाव और साम्प्रदायिक एकता कायम देखी गई है. यहां के शिक्षक अपने स्कूल की कक्षाओं में हिन्दू और मुस्लिम बच्चों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं. यहां के जिम्मेदार अफसर भी इतने सजग और चैतन्य है कि उन्हें हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव की कोई भावना कहीं दिखाई नहीं देती. इंसाफ करने और आम आदमी को मदद देने की भावना भी उनमें एक समान ही रहती है.

फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कौन से राजनीतिक दल और संगठन हैं जो कालीचरण जैसे अनजान व्यक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ की फिजां में जहर घोलना चाहते हैं. यदि समय रहते इनकी पहचान नहीं की गई और इनके पीछे की ताकतों को उजागर नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था को अशांत करने राजनीतिक लाभ उठाने की उनकी मंशा और साम्प्रदायिक आग से खेलने के मंसूबों को रोक पाना कठिन हो जाएगा. उनके कुप्रयासों की हवा बहुत दूर तक जाएगी.

चैतन्य बघेल
आशीष वर्मा
मनीष बंछोर
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़
मान. श्री गुरु रुद्र कुमार
मंत्री, छ.ग. शासन
मुख्यमंत्री के सपनों का बनेगा भिलाई-चरोदा निगम
अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने संकल्पित
ट्रांसपोर्ट नगर को व्यवस्थित करने की प्राथमिकता
मान. श्री भूपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
निर्मल कोसरे
महापौर, नगर पालिक निगम
भिलाई-चरोदा
कृष्णा चन्द्राकर
सभापति, नगर पालिक निगम
भिलाई-चरोदा

पुलिस की वर्दी में हार्डकोर अपराधी की तरह काम करने वाले आतंक के पर्याय बने लंबे समय से फरार निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गये. भ्रष्टाचार और राजद्रोह के मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने उन्हें गुड़गांव से गिरफ्तार कर रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया. अपनी गिरफ्तारी से स्तब्ध और बौखलाया 6 महीने से पुलिस को चकमा देने वाला यह आईपीएस अफसर अब आरोपों को नकारकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को चरितार्थ कर रहा है.

- **समानांतर टीम बनाकर हार्डकोर अपराधी की तरह करते थे वसूली**
- **चलेगा भ्रष्टाचार और राजद्रोह का केस**
- **14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर जेल**

- **हार्डकोर नक्सली पहाड़ सिंह के वसूली का मामला अभी भी दुर्ग आईजी के पास लंबित है.**
- **पहाड़ सिंह ने नोटबंदी के समय पुराने नोटों को बदलने जिन उद्योगपतियों को पैसा दिया था उनसे भी भयादोहन कर करोड़ों की वसूली की.**

जी.पी. सिंह आखिरकार गिरफ्तार

कानून को अपनी रखैल समझने वाले जीपी के खिलाफ पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति रखने और राजद्रोह के केस में जुर्म दर्ज किया था. ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा उनके रायपुर सहित कई ठिकानों पर मारे गए छापों में 10 करोड़ से अधिक नकदी समेत कई प्लाट फ्लैट, बैंक ड्राफ्ट आदि बेनामी संपत्ति जब्त की थी। वहीं एक डायरी समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे। वे पिछले 6 महीने से पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए निचली अदालत में सर्वोच्च न्यायालय तक नामी वकीलों के सहारे कानूनी राहत पाने का जुगाड़ तलाश रहे थे. लेकिन पुलिस ने उन्हें सीखचों के पीछे लाकर उनकी सारी कुचेष्टाओं पर पानी फेर दिया. अब पिंजरे में बंद घायल शेर की तरह संगीन आरोपों से घिरा यह निलंबित पुलिस अफसर अपने काले कारनामों पर शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय पुलिस को ही दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है. जो अफसर जिंदगी भर कानून की धाराओं से खेलते हुए अपने रौब और रसूख से वन टू का फोर करने का फर्जीवाड़ा करता रहा, अब वह खुद पुलिस के तमाम आरोपों को फर्जी बता रहा है. जबकि पांच एजेंसियां उनके वर्दी को दागदार करते हुए सफेदपोशों की मिलीभगत से उनके काले कारनामों के कच्चे चिट्ठे को बेनकाब कर चुकी है. जांच में वे पुलिसिया आतंक से अधिनस्थ लोगों के साथ रसूखदारों से करोड़ों की अवैध वसूली व आय से अधिक खर्च करने और राजद्रोह के आरोपी पाये गए हैं. याद रहे कि गिरफ्तार जीपी राजधानी सहित प्रदेश के बड़े जिलों में आईजी और फिर एडीजीपी रहते हुए आतंक के पर्याय बने हुए थे. रायपुर, बिलासपुर, भिलाई आदि में आईजी के कार्यकाल में उन्होंने अनेक उद्योगपतियों, जमीन के कारोबारियों और व्यवसायियों को वर्दी का रौब दिखाकर करोड़ों की अवैध वसूली की थी. बिलासपुर में जहां कोयला, कबाड़ी और चावल लॉबी से करोड़ों वसूले और एसपी राहुल शर्मा खुदकुशी प्रताड़ना मामले में जांच के दायरे में आए. वहीं भिलाई में कई जमीन दलालों का भयादोहन कर मोटा माल बनाया. अकेले भिलाई में ही कारोबारियों से सौ करोड़ से अधिक रुपए की वसूली की चर्चा है. कई जमीन व्यवसायियों की जमीनें भी अपने नाम करवा लीं. वसूली के लिये इस शातिर हार्डकोर अफसर ने बकायदा अपने ही विभाग के लोगों को धमकाकर एक गिरोह बना रखा था. वे आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं से खेलते हुये नवधनाढ्यों काले कारनामों में संलिप्त लोगों की संपत्ति को गलत तरीके से हड़पने और इसके लिए उन्हें झूठे केस में फंसा देने की कला में माहिर थे.

विभागीय जांच का हंटर

जीपी की कार्यशैली बिलकुल वैसी ही थी, जैसी अपराध जगत के किसी माफिया की होती है. यूपी बिहार, मुंबई व दिल्ली के कुख्यात भ्रष्ट पुलिस अफसरों की तरह निलंबित एडीजी खुद को प्रशासन और विभाग व कानून से ऊपर समझते थे. वसूली, दबंगई और संबंधितों को प्रताड़ित करने के लिये उन्होंने पुलिस के समानांतर अपनी निजी टीम बना रखी थी. विभागीय कर्मियों को वे विभागीय जांच का खौफ दिखाकर गैर कानूनी कार्यो को करने के लिए मजबूर करते थे. इस टीम का बड़े कारोबारियों से मोटी रकम वसूलना रोजमर्रे का काम था. सरकारी आदेशों की अवहेलना और झूठे केस में फंसाने की धौंस देकर उनकी संपत्ति को हड़पना उनके बायें हाथ का खेल था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस तरह के कई मामलों में जीपी के खिलाफ जांच चल रही है. जब्त डायरी में कुछ तत्कालीन राजनीतिकों व अफसरों से मिलीभगत के भी आरोप हैं. कई संगीन मामलों में अभी भी उनके खिलाफ कई जांच लंबित है. अवैध वसूली के शिकार उनके लोग शिकायत लेकर जांच एजेंसियों के पास पहुंच रहे हैं.

ॐ

भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग

भारती ग्रुप द्वारा संचालित

भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पिछले 23 वर्षों से विभिन्न संकायों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है...

पाठ्यक्रम

बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री (बी.आप्टम)
मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री (एम.आप्टम)

ऑप्टोमेट्री कोर्स में आंखों से संबंधित विषयों का अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें लो-विजन डिवाइसेज एवं विजन थेरपी, आई एक्सरसाइज, कॉन्टैक्ट लैंस आदि के बारे में शिक्षा प्राप्त होगा, ऑप्टोमेट्री अमेरिका जैसे डिवेलप देश में तीसरा बेस्ट प्रेस्टीजियस और मनी अर्निंग प्रोफेशन माना जाता है। जिसमें एक वर्ष का इंटर्नशिप होगा।

बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थैरेपी (बी.ओ.टी.)
मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थैरेपी (एम.ओ.टी.)

ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें मानसिक रोगी और मानसिक रूप से अक्षम हो चुके मरीजों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद से सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। इसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर, पार्टीश, लकवा, रीढ की हड्डी, मस्तिष्क की चोट, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे अन्य बीमारियों का इलाज ऑक्यूपेशनल थेरेपी से संभव है। जिसमें एक वर्ष का इंटर्नशिप होगा।

बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (बी.पी.टी.)
मास्टर ऑफ फिजियोथैरेपी (एम.पी.टी.)

फिजियोथेरेपी में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए व्यायाम, मालिश और अन्य तौर-तरीकों जैसे फिजिकल एजेंट का उपयोग करता है जिनके प्रोटेस्ट और कार्य को उम्र बढ़ने, चोट, अन्य बीमारी या अन्य कारकों से खतरा होता है। जिसमें छह महीने का इंटर्नशिप होगा।

प्रवेश पात्रता :- NEET (नीट) मैरिट के आधार पर प्रवेश, सीट रिक्त रहने पर विश्वविद्यालय स्तर में प्रवेश परीक्षा मैरिट के आधार पर प्रवेश I Course Duration : 4 Years Eligibility : 12th Biology / Maths

रोजगार :- फिजियोथेरेपिस्ट / ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट बनकर केंद्र एवं राज्य शासन के उपक्रमों एवं निजी संस्थाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते है जैसे-यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, बैंक, हॉस्पिटल एवं अन्य।

इंजीनियरिंग

एम.टेक./बी.टेक./डिप्लोमा

मैकेनिकल — माईनिंग
इलेक्ट्रीकल — डाटा माईनिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस — सिविल
इंफार्मेशन सिक्योरिटी — कम्प्यूटर
बिग डाटा — मेटेलर्जी

एम. आर्क बी.आर्क डी. आर्क
एम. प्लान बी. प्लान
एम. डिजाईन बी. डिजाईन
एम.आई.डी. बी.आई.डी.

आर्ट्स/साईस/ कॉमर्स

बी.ए. आनर्स — बी.कॉम. आनर्स
बी.एस.सी. आनर्स — एम.ए. (सभी विषय)
एम.एस.सी.(सभी विषय) — एम.कॉम.
डी.सी.ए. — बी.सी.ए.
बी.आर.एस — पीजीडीसीए
एम.आर.एस — एम.एस.डब्ल्यु.
बी.बी.ए. — एम.बी.ए.
पीजीडीबीए

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

- पैथोलॉजी (डीएमएलटी)
- एक्स-रे टेक्नोलॉजी
- रेडियो निदान
- ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी
- मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन
- योग साईस
- एनवायरमेंटल साईस
- फेशन डिजाईन
- इंटीरियर डिजाईन

एजुकेशन

एम.एड. बी.एड डी.एड.
एम.पी. एड. बी.पी.एड. डी.पी.एड.

लाईब्रेरी साईस

एम.लिब., बी.लिब., डी.लिब.

फार्मेसी

एम. फार्मा बी.फार्मा
डी.फार्मा

हेल्थ साईस

मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (M.P.H.)
मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिन (M.H.A.)

पी.एच.डी. (सभी विषय)

एम.फिल. (सभी विषय)

होटल मैनेजमेंट

बी.एच.एम. एम.एच.एम.

जर्नलिज्म

बी.ए. जेएमसी
एम.ए. जेएमसी

लॉ

बी.ए. एलएलबी
बी.कॉम. एलएलबी
एलएलबी एलएलएम

नोट: सभी विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ी एक विषय अनिवार्य है।
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा छात्रवृति प्रदान किया जाता है।

यूनिवर्सिटी कैम्पस
बालोद रोड, चंदखुरी, दुर्ग (छ.ग.)

डिविजन ऑफिस
भारती कॉलेज, पुलगांव चौक, दुर्ग

www.bhartiuniversity.org bhartiuniversity.in@gmail.com

संपर्क :- 7024134230 / 7024144230 / 9109910304

SURAJ ASSOCIATES

Partner with Amigos Technology

Authorized dealer for thermal printer for Utility

Dealing with android base billing technology, Manufacturere & supplier of thermal paper rolls, manpower supplier for call centers as well official's support

Suraj Prakash Chandrakar
Contact No. : 83057 10003

- Experience Teacher Staff
- Language Development
- Quality Education
- Good Infrastructure
- Computer Class Available
- Library Available

Your Child Deserve The Best Education

NURSERY AND CLASS-1st To 8th

शिक्षा के साथ संस्कार भी

Contact
90398 18757
79875 40785

Run by : Saras Shikshan Samiti, Regd. No. : 5313

SARAS VIDYALAYA

Ward-17, Vrinda Nagar, Camp-1, Post-Supela - 490023, Bhilai, Distt.-Durg (C.G.)

L. Kalidas
Head Master

Mr. Ramesh Kumar Mishra

कवर्धा की फिजां में साम्प्रदायिक जहर

- कहीं फैल न जाए कवर्धा की आंच
- साम्प्रदायिक ताकतें बिछा रहीं बारूदी सुरंगें

डॉ. रमन सिंह अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए किस हद तक जा सकते हैं यह सभी देख रहे हैं. रमन सिंह के बेटे का वीडियो पूरे देश ने देखा है. भारतीय जनता पार्टी इस घटना को बढाने की कोशिश कर रही है. यह प्रदेश शांति का प्रदेश है. भाईचारे का प्रदेश है. उसे स्थापित करने में सभी को सहयोग करना चाहिए.

-भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री

पिछले तीन साल इस सरकार के तुष्टिकरण की वजह से पूरे क्षेत्र में लोगों के मन में सरकार के मंत्री के प्रति आक्रोश है. इस घटनाक्रम में एकपक्षीय कार्रवाई की गई. दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होती तो मामले ने तूल न पकड़ा होता.

-डॉ. रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री

भोरमदेव की ऐतिहासिक नगरी कवर्धा का सामाजिक तानाबाना तार-तार हो रहा है. अक्तूबर 2021 के प्रथम सप्ताह में यहां हुए झंडा विवाद को केन्द्रित कर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें अब अपने चरम पर हैं. पूर्व मुख्यमंत्री के गृह नगर की फिजां में घुला यह जहर अब पार्टी स्तर से ऊपर उठ गया है. कांग्रेस के प्रभावशाली हिन्दू नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिशें की जा रही हैं. माता कौशल्या, माता शबरी और महंत घासीदास की पुण्यभूमि छत्तीसगढ़ में ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है.

सुरेश प्रसाद गुप्ता

कवर्धा में छिटपुट घटनाएं पहले भी होती रही हैं पर उन घटनाओं को कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया गया. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में भी घटनाएं हुईं पर उन्हें किसी ने भी तूल नहीं दिया. फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि न केवल यहां साम्प्रदायिकता की आग सुलगाई गई बल्कि देश भर से नेता, साधु और संत उसमें घी डालने पहुंच गए? जानकार इसे भाजपा की राजनीतिक पुनर्वास की कवायद से जोड़ कर देख रहे हैं.

दरअसल समूचा कवर्धा जिला कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर का कार्यक्षेत्र है. वे जिले की अलग-अलग सीटों से चार बार विधायक रह चुके हैं. 2 बार वीरेन्द्रनगर, एक बार कवर्धा तथा एक बार पंडरिया से चुनाव जीतकर उन्होंने स्वयं को पूरे जिले का नेता साबित कर दिया है. जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है. 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने रिकार्ड 60 हजार मतों से चुनाव जीत कर प्रदेश सहित पूरे देश में खलबली मचा दी थी. जीत का यह अंतर केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक था. ऐसा जनाधार रखने वाले नेता को मुस्लिम नेता कहने की गुस्ताखी की जा रही है.

2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी रिकार्ड मतों से जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस सीट पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. भाजपा के मुख्यमंत्री का यह गृह जिला है. भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय फायर ब्रांड नेता स्मृति इरानी, योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री), स्वयं डॉ रमन सिंह एवं उनके सांसद पुत्र अभिषेक सिंह ने यहां मोर्चा संभाला था. बावजूद इसके मो. अकबर की रिकार्ड मतों से जीत पार्टी को भीतर तक चोट पहुंचा गई.

दो साल बाद एक बार फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं. मोहम्मद अकबर को कवर्धा से हटाए बिना यहां भाजपा की दाल नहीं गलने वाली. इसलिए उसने अपना वही घिसा-पिटा साम्प्रदायिक कार्ड यहां भी खेल दिया. एक घटना को मुद्दा बनाकर उसपर राजनीति शुरू कर दी गई. हिन्दुत्व के नाम पर साधु संतों का जमावड़ा लगाया गया. हिन्दू होने का हवाला देकर लोगों के जमीर को ललकारा गया. इसका असर भी हुआ. बड़ी संख्या में हिन्दू नेताओं और कार्यकर्ताओं का भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया.

बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो गई. रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर देश भर में फैली नफरत को यहां भुनाने की कोशिश की गई. कवर्धा में उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर बस गए मुसलमानों को रोहिंग्या बताकर उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई. कवर्धा में ये मुसलमान कोई रातों रात नहीं आकर बस गए थे. भोरमदेव चीनी कारखान खुलने के पहले ही यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी. अब तो उनकी आबादी भी यहां लगभग 15 हजार की हो चुकी है. इनमें से 5-7 हजार लोगों के पास मतदान का अधिकार भी है.

हकीकत यह है कि ये मजदूर यहां गुड़ बनाने के लिए आए थे और यहीं के होकर रह गए. इनमें से अधिकांश मुसलमान हैं. आज यहां लगभग 450 कारखाने गुड़ बनाने के हैं जहां सर्वाधिक संख्या मुसलमान कारीगरों की ही है. चूंकि गुड़ बनाने का काम मौसमी होता है इसलिए ये मेहनत मशक्कत वाले दूसरे कार्यों को भी अपनाने लगे. आरोप लगा कि ये लोग कबाड़ी धंधे की आड़ में चोरी-चकारी में लग गए हैं. कांटेदार तार, किसान पम्प आदि की चोरी की घटनाओं के लिए अब इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा.

उपेक्षा से कांग्रेसी भी नाराज

मो. अकबर के खिलाफ भाजपा आरएसएस के लोगों के साथ कांग्रेसी और हिंदू समुदाय के कतिपय लोगों में भी नाराजगी है. कांग्रेसियों की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह कि मंत्री द्वारा ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है जिनकी जनता के बीच साफ-सुथरी छवि नहीं है. एक ही परिवार के दो-दो, तीन-तीन व्यक्ति को राजनीतिक पद दे दिए गए हैं. लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य करने वालों की उपेक्षा की जा रही है. इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मंत्री के खिलाफ बेहद नाराजगी है.

कहीं फैल न जाए आंच

कवर्धा में एक छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगाई गई साम्प्रदायिक नफरत की इस आग की लपटें सोशल मीडिया से होकर पूरे प्रदेश में फैल रही है. छत्तीसगढ़ की अब तक की पहचान एक शांति प्रिय प्रदेश की रही है जो तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रही है. जो भी लोग अन्य राज्यों से यहां आते हैं, यहां का सम्प्रदायिक सद्भाव और सौहार्द्र का माहौल उन्हें बेहद रास आता है. सरल स्वभाव के छत्तीसगढ़ी सभी को आत्मसात करते रहे हैं. यही कारण है कि कामगारों के साथ ही प्रतिनियुक्ति पर यहां आने वाले अधिकारी भी यहीं बस जाते हैं. यदि नफरत की आंधी की यही रफ्तार रही तो छत्तीसगढ़ का यह स्वरूप नष्ट हो सकता है.

भाजपा का काम कलह फैलाना है. भाजपा ने हमेशा से धर्म से धर्म को लडा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और देश-प्रदेश की सामाजिक समरसता भाईचारा, एकता, अखंडता को खंडित करने का काम किया है.

- धनंजय सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस

कुलपतियों की नियुक्ति में मनमानी कब तक ?

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षाविदों की कमी नहीं है. इसके बावजूद क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में बाहर के लोगों को कुलपति पद पर क्यों बिठाया जा रहा है. यह सवाल अब गहराता जा रहा है. राज्यपाल एक विशेष विचारधारा के लोगों को कुलपति बनाना चाहती है. यह विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस महत्वपूर्ण पद पर एक विचारधारा विशेष व छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों की पदस्थापनाओं को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद गहराता जा रहा है. इससे विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन के साथ ही विकास का काम भी प्रभावित हो रहा है. बीते 15 वर्षों से काबिज भाजपा सरकार की विदाई के तीन साल बाद भी छत्तीसगढ़ के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक विशेष विचारधारा और बाहर के कुलपति बनाए जाने से स्थानीय प्रतिभाओं के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है. सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या इन विशेष विचारधारा के लोग ही कुलपति नियुक्त किए जाएंगे? उच्च शिक्षा और अनुसंधान जैसे राज्य के विकास से जुड़े शैक्षिक संस्थानों में उच्च मानदंडों की अनदेखी कर भेदभाव करना कहां तक उचित है.

राजभवन की कार्यशैली पर उठे सवाल

विक्रम जनबंधु

छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है. छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आवाज उठानी होगी और संघर्ष भी करना होगा. छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए 21 साल हो गए हैं. लंबे संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़िया किसान मुख्यमंत्री भी मिल गया है, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ियों को विभिन्न स्थानों पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है. अकसर कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के पास उच्च पदों को धारण करने की योग्यता नहीं है. इसीलिए दूसरे राज्यों से प्रबुद्धजनों को उच्च पदों पर आसिन किया जा रहा है. ताजा मामला महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय सांकरा रायपुर के कुलपति चयन का है. वहां उत्तरप्रदेश के प्रोफेसर को कुलपति नियुक्त कर दिया गया है. राज्य सरकार ने जो नामों का पैनल बनाकर भेजा था, उसे राज्यपाल ने नजरअंदाज करते हुए अपने पसंद का कुलपति नियुक्त कर दिया है. यह एक मामला नहीं है, इसके पहले कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में भी इसी तरह की मनमानी देखने को मिली थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर तीखी टिप्पणी भी की थी. आखिर क्या कारण है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके को आदिवासी बहुल राज्य में कोई स्थानीय व्यक्ति कुलपति के लायक नहीं दिखता. जहां 50 प्रतिशत आबादी ओबीसी की है, वहां कोई इन पदों के लिये योग्य नहीं दिखता. आखिर क्या कारण है कि एक विशेष संगठन से नाता रखने वाला व्यक्ति ही कुलपति के लिए पात्र बनता है. चाहे उसका ट्रेक रिकार्ड कितना भी खराब क्यों न हो. वह कितने भी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हो.

छत्तीसगढ़ में कई विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस अहम पद पर एक विचारधारा विशेष और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों की पदस्थापना को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विवाद बढ़ रहा है इसके चलते विश्वविद्यालयों में अध्ययन

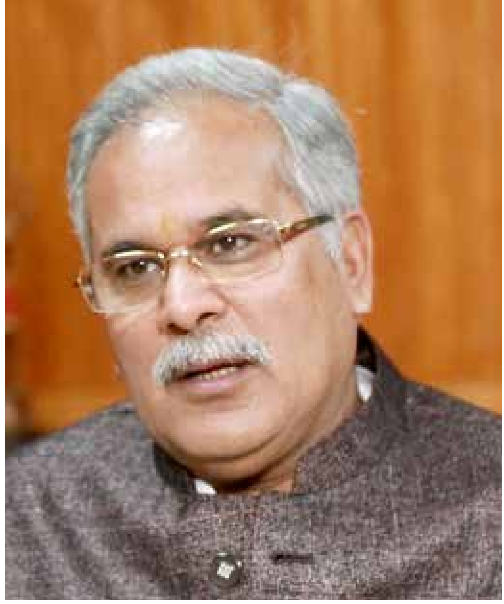

-अध्यापन के साथ विकास भी प्रभावित हो रहा है. छत्तीसगढ़ में पंद्रह वर्षों से काबिज भाजपा सरकार की विदाई के तीन साल बाद भी शिक्षा मंदिरों में न्याय नहीं हो पा रहा है. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक विशेष विचारधारा और बाहर के कुलपति बनाए जाने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल के बीच विवाद गहराया हुआ है. विवाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, पं सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर, अटलबिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर, नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, गहिरागुरु विश्वविद्यालय सरगुजा में संघी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को कुलपति बनाए जाने को लेकर है वहीं उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन में तो यूपी के एक ऐसे व्यक्ति को कुलपति बना दिया गया है जिस पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं. प्रदेश सरकार इन उच्च तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार और शोधपरक शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षित, योग्य और छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को कुलपति नियुक्त करना चाहती है लेकिन राज्यपाल विचारधारा विशेष के लोगों को ही इस पद पर बनाए रखने के पक्षधर हैं? सवाल इस बात का है कि क्या विशेष विचारधारा और पृष्ठभूमि के लोग ही कुलपति नियुक्त किए जाएंगे शिक्षा और अनुसंधान जैसे राज्य के विकास से जुड़े शैक्षिक संस्थानों में मानदंडों की अनदेखी कर इस तरह का भेदभाव कहां तक उचित है. देश में पहले ही केंद्र सरकार ने पचास-साठ विश्वविद्यालयों में आईएएस ग्रेड के सचिव स्तर के निर्णायक पदों पर एक विशेष विचारधारा से जुड़े लोगों को बिठा रखा है, अब छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में इस परंपरा को बढ़ाया जा रहा है. पांच विश्वविद्यालयों में से कई में पहले से राज्य में भाजपा शासन के दौरान से अपनी विचारधारा के लोगों को कुलपति नियुक्त किया गया गया और अब कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी इस मामले में राज्यपाल के जरिए दखलंदाजी से मोदी सरकार परहेज नहीं कर रही है इस विसंगति के चलते कई विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बने हुए हैं. कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में दस वर्ष तक कुलपति रहे पाटिल का कार्यकाल पूर्ण होने पर और यूपी मूल के डॉ. एसएस सेंगर को 6 माह के लिए प्रभारी कुलपति नियुक्त कर दिया गया है. पाटिल को तत्काल यहां संचालक कृषि अनुसंधान बना दिया गया है यह पद कुलपति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद है. इस मामले में आपत्ति इस तथ्य को लेकर जताई जा रही है कि कुलपति चयन के लिए गठित कमेटी की सिफारिश को दरकिनार कर राज्यपाल ने केंद्र सरकार के सुझाए व्यक्ति को कुलपति बना दिया, जबकि चयन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी राज्यपाल ने ही बनवाई थी. कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, आईएएस सुबत साहू, समाजवादी नेता आनंद मिश्रा सदस्य थे. लेकिन कुलपति चयन में कमेटी के सुझाए नामों को ही महत्व नहीं दिया गया. क्या ऐसा इस लिये किया गया, क्योंकि राज्यपाल भी एक विशेष विचारधारा की हैं और उन्हें केंद्र सरकार ने ही राज्यपाल बनाया है. पिछले 35 साल से कृषि विवि में किसी स्थानीय व्यक्ति को कुलपित नहीं बनाया गया है आखिर सिर्फ एक विचारधारा के व्यक्ति को कुलपति बनाकर विश्वविद्यालय और युवा पीढ़ी का किस तरह की विकास केंद्र सरकार चाह रही है सच तो यह है कि दस वर्ष से कृषि विवि में कुलपति के पद पर काबिज पाटिल को आगे बहाल करने में वैधानिक दिक्कतों को देखते हुए ही उन्हें दूसरे नंबर के संचालक जैसे अहम पद पर बिठा दिया गया, जबकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, क्या उन्हें छह महीने बाद फिर से कुलपति बना दिया जाएगा या फिर प्रभारी कुलपति डॉ. सेंगर को पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त कर दिया जाएगा. आखिर छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को अवसर कब मिलेगा प्रभारी कुलपति से लंबे समय तक काम चलाने से किसका भला होगा कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की तरह कृषि एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय पाटन की स्थापना के एक साल बाद भी कुलपति का चयन नहीं किया जा सका हाल ही में इस विश्वविद्यालय में भी राज्यपाल द्वारा ऐसे विवादित व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के हैं. इतना ही नहीं उन पर 45 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप भी है क्या इस तरह की विसंगति और भेदभाव न्यायोचित्त है? कृषि प्रधान राज्य में कृषि विश्वविद्यालय में इस तरह का पक्षपात व उपेक्षा कहां तक न्यायोचित है. फुलफ्लैश कुलपति नियुक्त नहीं हो पाने से विश्वविद्यालय को चौतरफा नुकसान हो रहा है. विश्वविद्यालय में सिर्फ कांक्रीट का विस्तार किया जा रहा है. इसके चलते राज्य सरकार

डॉ. कुरील, अटल बिहारी वाजपेयी विवि बिलासपुर के कुलपति के साथ

आज की मांग स्थानीय कुलपति

राज्य के विश्वविद्यालयों में योग्य और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के जानकार व्यक्ति को कुलपति बनाए जाने से शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कृषि का भी विकास तेजी से होगा धान व अन्य फसलों के अनुसंधान और कौशल्यता को विकसित करके ही उन्नत खेती का विकास कर राज्य का विकास किया जा सकता है. यह तभी संभव है जब विश्वविद्यालय में योग्य और यहां की ग्राम्य आबोहवा और खेती-किसानी को बखूबी समझने वाले व्यक्ति को कुलपति बनाया जायें इससे किसान जहाँ उन्नत तकनीकों व विकासोन्मुखी कृषि से परिचित होंगे वहीं नए-नए अनुसंधानों से यहां के युवाओं को रोजगार और खेती-किसानी को बेहतर करने का भी अवसर मिलेगा.

नियम विरुद्ध है सेंगर को प्रभार सौंपना

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में डॉ एस.एस. सेंगर को कुलपति पद का प्रभार सौंपना विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के विरुद्ध है. अधिनियम की धारा 14(7) में स्पष्ट प्रावधान है कि कुलपति की मृत्यु या उसके पद त्याग करने जैसी किसी भी आकस्मिक स्थिति में इस पद पर प्रभारी नियुक्त किये जा सकते हैं. ऐसे प्रभारी का कार्यकाल अधिकतम 6 माह का हो सकता है. अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक इस पद पर प्रभारी के रूप में वरिष्ठतम निदेशक, किसी संकाय का अध्यक्ष या सरकार के किसी आई.ए.एस. अधिकारी की ही नियुक्ति की जा सकती है. प्रभार की यह अवधि अधिकतम छह माह की होगी. अधिनियम की उपधारा (1) के तहत नए कुलपति की नियुक्ति के साथ ही यह प्रभार समाप्त हो जाएगा.

उल्लेखनीय है कि डॉ एस.एस. सेंगर न तो विश्वविद्यालय के निदेशक हैं और न ही किसी संकाय के अध्यक्ष हैं. वे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मात्र हैं. इसके अलावा उनके पास निदेशक शिक्षण का अतिरिक्त प्रभार है.

इससे पहले तत्कालीन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती रही हैं. प्रत्येक बार यह प्रभार शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी को ही सौंपा गया है. वर्ष 1995 में संभाग आयुक्त रायपुर जे.एल. बोस तथा आयुक्त बिलासपुर एस.पी.दुबे यह जिम्मेदारी उठा चुके हैं. वर्ष 1997-98 में पुनः यह जिम्मेदारी आयुक्त रायपुर जे.एल. बोस को सौंपी गई. छत्तीसगढ़ बनने के बाद वर्ष 2003 में कृषि उत्पादन आयुक्त आर.पी. बगई को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. 2008 में तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त सरजियस मिंज ने इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया. वर्ष 2011 में एक बार फिर ऐसी ही स्थिति बनी और तब तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त डी.एस. मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई.

और राज्यपाल के बीच टकराव भी बढ़ रहा है राज्य के बाहर के लोगों को कुलपति बनाए जाने के प्रयास से स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ने से भी देश में गलत संदेश जा रहा है. आखिर राज्यपाल व राज्य सरकार के बीच क्षेत्राधिकार के बीच खिंची लक्ष्मणरेखा को लेकर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है.

राजभवन क्यों कर रहा मनमानी

राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में पक्षपात और विसंगति को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है राज्यपाल द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्ती नगर पंचायत और नगर पालिका बनाए जाने पर सख्त ऐतराज जताया था. उनकी इस तल्खी पर पलटवार करते हुए बालोद के ही मंच में सीएम ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि राज्यपाल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों की नियुक्ति को प्राथमिकता क्यों नहीं देतीं क्या छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी है. राज्यपाल को नियुक्ति का अधिकार है तो वे छत्तीसगढ़ियों की नियुक्ति क्यों नहीं करती है? कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है तो कोई दिल्ली तो कोई झारखंड से. छत्तीसगढ़ में जितनी नियुक्तयां हो रही हैं छत्तीसगढ़ियों की नहीं हो रही है.

महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिखा खींचतान का असर

विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल एवं सरकार के बीच जारी रस्साकशी का असर हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिखा. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन नवीन शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए किया गया था. कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा राज्य के कृषि मंत्री, स्थानीय विधायकों के अलावा प्रदेश के 10 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आमंत्रित किया गया था. मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम शामिल होने के लिए पहले ही मना कर चुके थे. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और स्थानीय विधायक सत्यनारायण शर्मा, अनिता शर्मा ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बना ली. आमंत्रित किये गए 10 में से केवल 4 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने ही शिरकत की.

कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा मेजबान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉ. एस.एस. सेंगर, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ मुकेश वर्मा, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर.एस. कुरील एवं कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एन.पी. दक्षिणकर ही उपस्थित हुए. इसके अलावा विश्वविद्यालय के बोर्ड मेम्बर बोधराम कंवर, आनंद मिश्रा एवं श्रीमती बल्लरी चंद्राकर भी उपस्थित हुए. शेष सभी आमंत्रितों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी.

यशस्वी नेतृत्व का कमाल
छत्तीसगढ़ में न्याय के तीन साल
सभी प्रदेशवासियों को
छत्तीसगढ़ के अभिमान के
3 वर्ष पूर्ण होने पर
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
हरेन्द्र राय
सुरेन्द्र राय
राम कुमार राय
मनोज कुमार यादव
मनोज रोडलाइन्स
ट्रांसपोर्ट नगर, भिलाई
मनोज ट्रेव्हल्स
भिलाई
यादव कृषि फॉर्म
ग्राम-रुही, जामगांव (एम)

क्यों हटाई गई तुलसी साहू?

विजय प्रताप कश्यप

एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने "लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ" का नारा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने की आवाज बुलंद की है. वहीं दूसरी ओर चुनाव में महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट देने का वादा भी किया है. लेकिन छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को ठेंगा दिखाकर गुटबाजी, साजिश और षड्यंत्रकारी लोगों ने जब भी विधायक टिकट देने की बारी आई वर्षों से पार्टी के लिए समर्पित और निस्वार्थ भाव से सेवारत महिला को पीछे धकेलकर किसी किचन से महिला को लाकर महापौर, विधायक बना दिया तो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पुरूष को सामने खड़ा कर दिया. तुलसी साहू के साथ ऐसा ही हुआ जो आजकल अपनी वकालत की प्रेक्टिस करने पर मजबूर हो गई हैं. आखिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक महिला की कौन सी योग्यता देखकर उसका मूल्यांकन करना चाहती है?

एक तेजतर्रार पेशे से वकील पढ़ी लिखी पिछले 30 सालों से कांग्रेस की सेवा में रत दुर्ग ग्रामीण की पूर्व जिला अध्यक्ष तुलसी साहू को भिलाई नगर जिलाध्यक्ष पद से क्यों हटाई गई यह आज भी रहस्य बना हुआ है? शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नज़र अपने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर नहीं है, जो पार्टी के षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार बन रहे हैं. आखिर इस साजिश के पीछे कौन से तत्व हैं जो मुख्यमंत्री और पार्टी को बदनाम करने के लिए मंसूबों में लगे हैं. इसकी पड़ताल उन्हें करनी चाहिए?

गुंडरदेही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 1994 व 2004 में लड़ चुकी तुलसी साहू तब ताराचंद साहू की पुत्री झमिता साहू से चुनाव हार गई थीं. 2010 में उनके भिलाई नगर निगम में महापौर बनने का अवसर आया तो राजनीति से अनजान किचन की रानी निर्मला यादव को महापौर टिकट दे दिया गया. तब वे दुर्ग जिला ग्रामीण महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थीं. लेकिन उनके हक पर

● छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र जारी!

● महिला की कौन सी योग्यता देखकर उनका मूल्यांकन होता है?

डाका डालकर उन्हें महापौर पद से वंचित कर दिया गया, जबकि वे महापौर पद की प्रखर दावेदार थीं.

सन् 2000 में भी वे महापौर पद की प्रबल दावेदार थीं लेकिन उन दिनों बदरूद्दीन कुरैशी का राजनीति में बोलबाला था, सो उनके कहने पर किचन की मल्लिका नीता लोधी को भिलाई नगर निगम का टिकट दे दिया गया.

2018 में बदरूद्दीन कुरैशी एक बार फिर तुलसी साहू के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए और वे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए प्रबल दावेदार थी जबकि बदरूद्दीन कुरैशी भिलाई नगर से. परंतु बदरूद्दीन कुरैशी को वैशाली नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर श्रीमती साहू की दावेदारी को समाप्त कर दिया गया. यह अलग बात है कि श्री कुरैशी यहां से चुनाव

साजिश के पीछे कौन

भूपेश बघेल सरकार का अब तक का कार्यकाल बेदाग और उपलब्धियों भरा रहा है. यहां तक कि विपक्ष को एक बार फिर धर्मांतरण रैली की शरण में जाना पड़ा है. ऐसे में तोड़फोड़ की राजनीति की संभावनाएं अपने आप बन जाती हैं. पर यदि ये तत्व संगठन और सत्ता के फैसलों को प्रभावित करने में कामयाब होते चले गए तो संकट के बादल घिर सकते हैं. इसलिए इस बात का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन लोग है.

हार गए और भाजपा प्रत्याशी विद्यारतन भसीन यहां से दूसरी बार चुनाव जीत गए.

बेहद लचर दलीलें

एक कारण यह बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के दुर्ग दौरे में तुलसी साहू का बढ़चढ़कर हिस्सा लेना उन्हें ले डूबा. सिंहदेव राज्य के केबिनेट मंत्री हैं और तुलसी साहू भिलाई नगर जिला कांग्रेस की अध्यक्ष. उन्हें तो कार्यक्रम में जाना ही था. इसे गुटबाजी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. यह भी दलीलें दी जा रही हैं कि चखना सेन्टर आबंटन में तुलसी की भूमिका कुछ लोगों को बेहद नागवार गुजरी है. पर इस आरोप का भी कोई सिर-पैर नहीं है.

आखिर क्या चाहती है पार्टी?

प्रदेश में सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की वैसे ही कमी है. ऐसे में पार्टी महिला कार्यकर्ताओं में क्या देखना चाहती है- यह एक यक्ष प्रश्न है. पेशे से वकील एक तेजतर्रार पढ़ी लिखी महिला को सालों इंतजार करना पड़ता है जबकि घरेलू महिलाएं पिछले दरवाजे से आकर महत्वपूर्ण पदों पर बैठ जाती हैं. जब उन्हें कोई पद मिलता भी है तो उसे कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया जाता. उलटे उसे एक ऐसा पद ऑफर किया जाता है जो उसकी सक्रिय राजनीति का तो पटाक्षेप करे ही, उसकी रोजीरोटी भी छीन ले.

उल्लेखनीय है कि तुलसी को महिला आयोग के संवैधानिक सदस्य का पद ऑफर किया गया. इसे स्वीकारने का मतलब था फकत 10 हजार रुपयों के लिए अपना कार्यक्षेत्र और वकालत छोड़कर खुद को चुपचाप एक दफ्तर में समेट लेना. तुलसी न इसे स्वीकार कर सकती थी और न किया.

नंदकुमार बघेल ने मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत

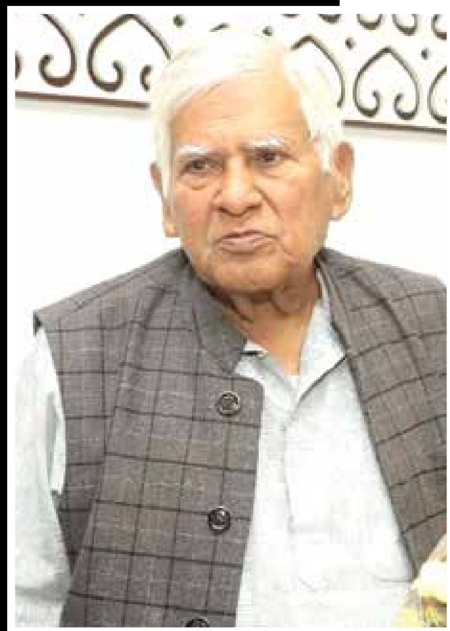

राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के अध्यक्ष नंद कुमार बघेल ने आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है. राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने अन्यथा इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मार्मिक अपील की है. उन्होंने इसके लिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को इच्छा मृत्यु का वरण करने की बात कही है. 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है.

राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में श्री बघेल ने कहा है कि आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा की पहली सीढ़ी उसके मतदान के अधिकार की सुरक्षा है. मतदान का अधिकार तभी पूर्ण हो सकता है जब उसे इस बात की गारंटी हो कि जिसे उसने मत दिया है, वह मत उसे ही मिला भी है. उन्होंने कहा कि ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) से मतदान कराने पर मतदाता तो क्या, खुद प्रशासन भी इसकी तसदीक नहीं कर सकता कि वोट गया किसे है. कुछ समय पूर्व इसके लिए वीवीपैट (Voter Verified Paper Audit Trail) मशीन का उपयोग प्रारंभ किया गया. पर यह सुविधा भी चंद बूथों तक ही संभव हो पाई.

ईवीएम के बजाय बैलेट से हों चुनाव

रिटायर्ड जजों को लाभान्वित करना गलत

श्री बघेल ने कहा कि ईवीएम का उपयोग तकनीकी रूप से विकसित देश भी नहीं करते. उन्हें अपने मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा की चिंता है. जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है. चुनाव आयोग कहता है कि इससे चुनाव के कार्य में तेजी आती है और गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है. पर गड़बड़ी नहीं हुई, इसकी तसदीक कौन करेगा? कैसे करेगा?

उन्होंने कहा कि स्वयं चुनाव आयोग में नियुक्तियां विवाद में रही हैं. ऐसे में कैसे मान लें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करेगा. मतदाता ने जिसे अपना वोट दिया, उसी को मिला या नहीं, उसकी पुष्टि केवल मतपत्र और मतदान पेटियों से ही किया जाना संभव है.

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 700 से अधिक किसानों की मृत्यु शासन की गलत नीतियों के चलते हुई है. इसे हत्या भी कहा जा सकता है. आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अदालतें इसका संज्ञान क्यों नहीं लेतीं?

श्री बघेल ने आगे कहा है कि देश में आम नागरिकों का अधिकार हाशिए पर चला गया है. लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका ध्वस्त हो रहे हैं. मीडिया ने इनके साथ गठजोड़ कर लिया है. सभी ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में लगे हैं. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल नियुक्त किये जा रहे हैं, राज्यसभा में सांसद बनाए जा रहे हैं. यह गठजोड़ नहीं तो और क्या है? ऐसे में देश का आम नागरिक खुद को बेहद लाचार महसूस कर रहा है. उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा. उसे न्याय नहीं मिल रहा है. ऐसे माहौल में वे घुटन का अनुभव कर रहे हैं.

राष्ट्रपति से उन्होंने दरख्वास्त की है कि कम से कम आम नागरिक के सही सरकार चुनने के अधिकार की रक्षा का वे आश्वासन दें. यदि ऐसा करना संभव नहीं होता तो उन्हें 25 जनवरी को इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने की इजाजत दें.

बीरगांव (सीट-40)

कांग्रेस पार्षद : 19
बीजेपी पार्षद : 10
निर्दलीय : 06
जोगी कांग्रेस : 05

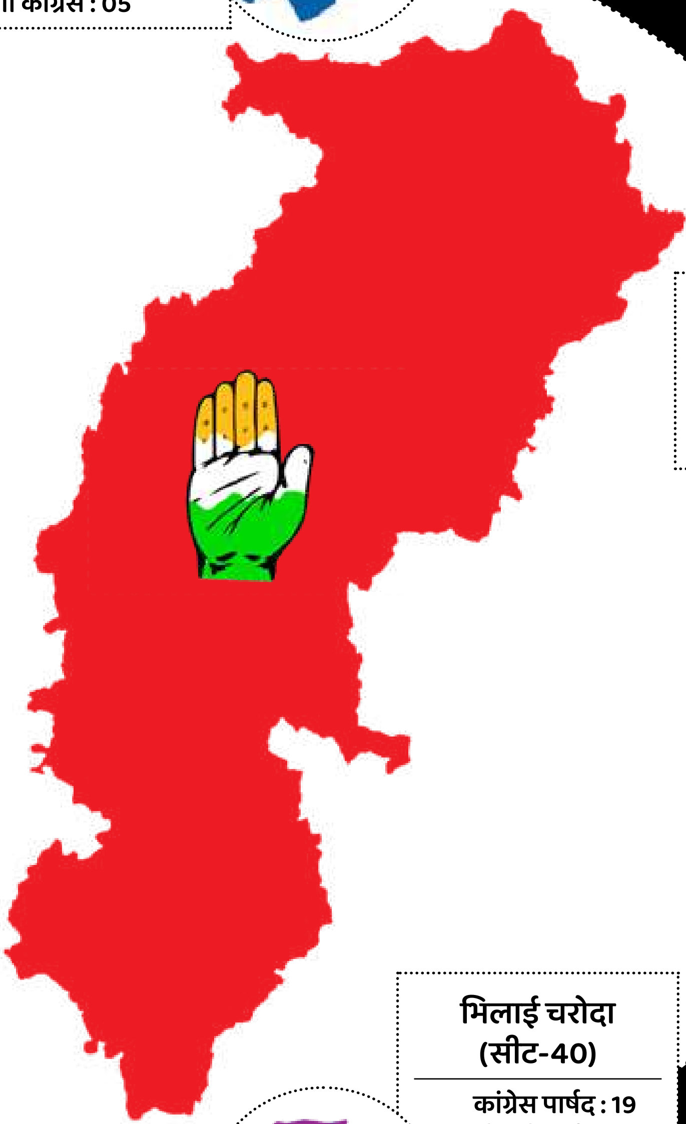

भिलाई (सीट-70)

कांग्रेस पार्षद : 36
बीजेपी पार्षद : 25
निर्दलीय : 09

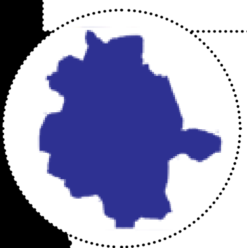

रिसाली (सीट-40)

कांग्रेस पार्षद : 21
बीजेपी पार्षद : 12
निर्दलीय : 07

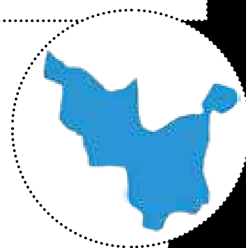

भिलाई चरोदा (सीट-40)

कांग्रेस पार्षद : 19
बीजेपी पार्षद : 15
निर्दलीय : 06

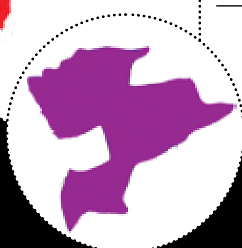

नगर निगम चुनाव

पंजा का परचम

जय-जयकार नगर सरकार

प्रदेश के हाईप्रोफाइल दुर्ग जिले के तीन बड़े निकायों के चुनावों में कांग्रेस ने परचम फहराकर एक बार फिर से खुद को अपराजेय साबित कर दिखाया है. पिछले विधानसभा चुनाव के महज तीन साल बाद पार्टी को मिली इस जीत को दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमी फायनल माना जा रहा है. जीत से उत्साहित कांग्रेस नेता मानकर चल रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव में भी इस प्रदर्शन को दोहराएगी वहीं निकाय चुनाव में शिकस्त से सहमी भाजपा पराजय की समीक्षा में जुट गई है. प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस के लिए निकाय चुनावों के नतीजे भले ही कई मायने में उत्साहवर्धक हों लेकिन मिनी विधानसभा चुनाव के परिणाम ने भाजपा की तरह कांग्रेस की अंतरकलह को भी सतह पर ला दिया है. यदि समय रहते भीतरखाने के इस अंतरद्वंद्व को नहीं सुना गया तो बाजी पलटने देर नहीं लगेगी.

छत्तीसगढ़ आजतक ब्यूरो

निश्चित रूप से निकायों की जीत कांग्रेस के लिए कई अर्थों में अहम है. भिलाई, रिसाली और भिलाई चरौदा तीनों नगर निगम में वार्ड चुनाव जीत के बाद अब पार्टी सभी जगह अपने महापौर और सभापति बनाने में भी कामयाब रही है. भिलाई निगम में नीरज पाल महापौर और सभापति गिरवर साहू तथा रिसाली में महापौर शशि सिन्हा तथा केशव बंछोर सभापति चुने गए. वहीं भिलाई चरौदा में निर्मल कोसरे महापौर और कृष्णा चंद्राकर सभापति निर्वाचित हुए हैं. जामुल पालिका में कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी है. तीनों निकायों में कांग्रेस की इस जीत की खास वजहें रही हैं और इसके मायने भी उतने ही खास हैं. निस्संदेह इसके दूरगामी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी कम नहीं है. पहले बात जीत के कारणों की कर लेते हैं. जीत की एक बड़ी वजह अनुकूल माहौल, नेतृत्व कौशल, सांगठनिक मजबूती और रणनीतिक सूझबूझ को माना जा रहा है. दुर्ग जिला सीएम भूपेश बघेल के साथ केबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू और गुरु रुद्रकुमार का भी गृह जिला है . केबिनेट मंत्री रवींद्र चौबे का भी यहां खासा प्रभाव है. फिर प्रदेश में कांग्रेस की तीन साल से सत्ता है, जनमानस पर विकास के साथ छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की भी खासी छाप है. लिहाजा मतदाताओं की सोच रही कि प्रदेश की तरह यदि नगर में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निर्बाध रूप से बजट आने से तेजी से विकास होगा. यानी जिले की सियासी पृष्ठभूमि और माहौल जीत के लिए कांग्रेस के अनुकूल था. इसके अलावा पार्टी ने टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक चुनावी तैयारी में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, जिसका बखूबी लाभ उसे मिला. भिलाई में चुनाव की कमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित पांच साल मेयर रहे विधायक देवेंद्र यादव, उनके भाई व प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र यादव और भजन सिंह निरंकारी, बीडी कुरैशी जैसे दिग्गज नेताओं ने संभाल रखी थी. रिसाली में खुद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने पुत्र प्रदेश मंत्री

जितेंद्र साहू व पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह व पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे. इसी तरह भिलाई चरौदा में भी सीएम श्री बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल मोर्चाबंदी किए हुए थे. इतना ही नहीं खुद सीएम विनिंग केंडीडेट के चयन और प्रचार से लेकर पार्टी की शहर सरकार बनाने तक चुनावी बागडोर थामे हुए थे. फिर निकायों के साथ आगामी विधासभा चुनावों को देखते हुए बेहतर नतीजे के लिए एक बड़े वोट बैंक को कैप्चर करने जातिगत व सामाजिक संतुलन बिठाते हुए न सिर्फ टिकट वितरण किया गया बल्कि मेयर सभापति बनाने में भी इसी फार्मूले को अपनाया गया. जमकर चला लोकलवाद, छत्तीसगढ़ियावाद और समाजों को साधने की इस पुरजोर कोशिश का ही सुफल था कि राजधानी से लगे बीरगांव नगर निगम के निर्वाचित महापौर कोष्टा समाज के नंदलाल देवांगन और केंवट समाज के सभापति कृपाराम निषाद की तरह दुर्ग जिले के तीनों निकायों में भी लोकलवाद का बोलबाला रहा. भिलाई चरौदा आरक्षित सीट से सतनामी समाज के निर्मल कोसरे को महापौर और कुर्मी समाज के कृष्णा चंद्राकर को निगम अध्यक्ष बनाया गया. इसी तरह रिसाली निगम में कलार समाज की शशि सिन्हा को महापौर तथा कुर्मी समाज के केशव बंछोर को सभापति के रूप में अवसर दिया गया. जबकि विभिन्न भाषाभाषी और समाजों वालें लघुभारत के रूप में प्रसिद्ध भिलाई में नीरज पाल को महापौर और तेली समाज के गिरवर साहू को सभापति बनाया गया. ज्ञात हो कि यहां 24 प्रतिशत कुर्मी, 22 प्रतिशत तेली, 4 प्रतिशत कलार और 4 प्रतिशत केंवट व 12 लाख कोष्टा जाति के लोग हैं. यानी 15 साल के निर्वासन के बाद कांग्रेस जिस छत्तीसगढ़ियावाद के चुनावी नारे के साथ प्रदेश में सत्तासीन होने में सफल हुई, उसी भावनात्मक जुमले को निकाय व आगत विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रयोग में लाया गया, जिसमें पार्टी पूरी तरह सफल रही. पार्टी को उम्मीद है कि इसका लाभ उसे आगामी विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा. यह संगठन के नेतृत्व की रणनीतिक सूझबूझ ही थी कि भिलाई निगम में कांग्रेस के 37 पार्षद (7 निर्दलीय भी कांग्रेस में शामिल) रिसाली में 21 और भिलाई तीन चरौदा में 19 पार्षद विजयी हुए.

भाजपा को भारी पड़ी गुटबाजी

जिले के 4 निकाय चुनाव में मात्र 3 साल पूर्व तक प्रदेश में 15 साल तक सत्ता सुख भोग चुकी भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. 4 में से 3 निकाय में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. एकमात्र जामुल पालिका में मिली जीत से उसे संतोष करना पड़ा. भिलाई चरौदा तो उसके हाथ से निकला ही भिलाई में भी उसे तीसरी बार पराजय झेलनी पड़ी. पार्टी पर गुटबाजी भारी पड़ी. भाजपा टिकट वितरण के दौरान आपसी समन्वय का दावा करती रही लेकिन गुटीय राजनीति ने इस दावे को खोखला साबित कर दिया. जिले में पार्टी दो गुटों और कई उप-गुटों में बंटी हुई है. मुख्य रूप से संगठन राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय और पूर्व केबिनेट मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय के गुटों में बंटा हुआ है. जिला भाजपा में सरोज का वर्चस्व है. इसके अलावा सांसद विजय बघेल और विधायक विद्यारतन भसीन के भी उप गुट हैं. लेकिन जीत के लिए शीर्ष नेतृत्व की समझाईश के बाद चुनाव के कुछ दिन पूर्व दोनों गुट एक होते दिखे, प्रचार भी साथ किया और टिकट वितरण में भी संतुलन दिखा. लेकिन मतदान और महापौर चुनाव तारीख के आते-आते दिखाई देने वाली यह एकता टूट गई. वार्ड चुनाव में जहां पार्टी के अल्प प्रत्याशी जीत (भिलाई-25, रिसाली-12, भिलाई चरौदा-15 व जामुल-10) सके वहीं महापौर चुनाव में भी उसे रिसाली में क्रास वोटिंग का सामना करना पड़ा. विरोधी गुट के नेताओं ने आरोप लगाया कि दोनों पार्षदों को टिकट सांसद विजय बघेल की अनुशंसा पर मिला था जिसे बघेल ने खारिज किया. हालांकि कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी अधिकतर सीनियर पार्षदों की टिकट काटी थी लेकिन विनिंग केंडीडेट को टिकट देने में असावधानी और भीतरघात भारी पड़ा और कांग्रेस को सत्ता का लाभ भी मिला. एक वजह यह भी बताई जा रही है कि चुनाव की कमान संभालने वाले प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक, सरोज पांडेय, प्रेमप्रकाश पांडेय, विजय बघेल और बृजमोहन अग्रवाल ने खुलकर प्रत्याशियों के पक्ष में कांग्रेस की तरह प्रचार नहीं किया. यदि भाजपा की गुटबाजी का आगे भी यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

सामान्य की उपेक्षा से बगावत

कांग्रेस को भिलाई महापौर चुनाव में लगातार दूसरी बार आरक्षित प्रत्याशी के मामले में उपेक्षा महंगी पड़ी. इस मामले में यदि पार्टी ने ऐन मौके पर रणनीतिक सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो दांव उलटा भी पड़ सकता था. भिलाई निगम महापौर पद पिछली बार की तरह इस चुनाव में भी सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था. लेकिन पिछली बार ओबीसी महापौर देवेंद्र यादव की तरह पार्टी द्वारा इस चुनाव में भी ओबीसी से अपना महापौर प्रत्याशी एकांश बंछोर को मैदान में उतारे जाने की चर्चा थी. सामान्य वर्ग के प्रमुख दावेदारों की दलील थी कि जब ओबीसी या एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट से सामान्य वर्ग का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता तो फिर सामान्य वर्ग की सीट भिलाई से सामान्य वर्ग के पार्षद को ही महापौर बनाया जाए. इस मुद्दे को लेकर भाजपा की खरीदफरोख्त से बचने सुरक्षाबंदी में बाहर भेजे गए कांग्रेस पार्षदों के बीच तकरार होती रही. वरिष्ठ और पहली बार जीते पार्षदों के बीच भी दावेदारी को लेकर विवाद होता रहा. वरिष्ठों को ही महापौर बनाने का दबाव सीनियर पार्षद पर्यवेक्षक पर डालते रहे. इसे देखते हुए सीएम ने एक दिन पहले सीनियर और अन्य वर्ग के नीरज पाल का महापौर प्रत्याशी के रूप में चयन किया. लेकिन चुनाव के दिन 4 बार की पार्षद सामान्य वर्ग की सुभद्रा सिंह ने खुद की दावेदारी पेश करते हुए नामांकन भरने की तैयारी कर दी. लेकिन प्रस्तावक व समर्थक निर्दलीय पार्षदों के खुद प्रत्याशी व समर्थक होने व बड़े नेताओं की समझाईश के बाद उन्होंने नामांकन नहीं भरा. यदि ऐन मौके पर कांग्रेस नेता सजगता नहीं दिखाए होते तो भाजपा, निर्दलीय और कांग्रेस की क्रास वोटिंग से दांव उलटा पड़ सकता था.

रिसाली व जामुल में दांवपेंच

कांग्रेस को रिसाली और जामुल पालिका में प्रत्याशी तय करने से लेकर जीत तक कई दांवपेंच आजमाने पड़े. पहली बार रिसाली नगर निगम में हो रहे चुनाव के लिए निगम के गठन, विकास से लेकर आरक्षण और प्रत्याशी चयन तक क्षेत्रीय विधायक व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की केंद्रीय भूमिका रही. रिसाली महापौर का पद महिला ओबीसी के लिए आरक्षित होने के बाद से ही यह चर्चा रही कि वे अपनी बहू को यहां से महापौर चुनाव

लड़ाना चाहते हैं. 4 महीने पहले उनकी बहू की सक्रियता भी बढ़ गई थी और उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया था कि यदि पार्टी टिकट देगी तो वे अवश्य चुनाव लड़ेंगी. लेकिन बताते हैं कि प्रदेश शीर्ष नेतृत्व के रिश्तेदारों को प्रत्याशी नहीं बनाने और निगम में खुलकर कुर्मी तेलीवाद से बचने की समझाइश के बाद इरादा बदलना पड़ा. कुर्मी बहुल क्षेत्र रिसाली निगम से समाज के लोग कुर्मी समाज की महिला को महापौर प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहे थे. लेकिन पार्टी ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत इस डर से एक भी कुर्मी महिला को टिकट नहीं दिया कि जीतने पर उनकी दावेदारी बढ़ जाएगी. सर्वाधिक जनसंख्या वाले कुर्मी व साहू जाति को दरकिनार कर ओबीसी वर्ग से ही कलार समुदाय से शशि सिन्हा को महापौर प्रत्याशी बनाकर उसकी जीत पर मुहर लगाई. इसके पहले ताम्रध्वज साहू की रिश्तेदार पार्षद डॉ. सीमा साहू भी प्रबल दावेदार बताई जा रही थीं लेकिन पार्टी की सजगता और रणनीति के तहत भिलाई की तरह रिसाली में भी प्रत्याशी बदलना पड़ गया. रिसाली निगम के महापौर प्रत्याशी की तरह जामुल में भाजपा में भी उथलपुथल चलती रही. जामुल में पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखराम बंछोर का नगर व पार्टी में प्रभाव होने से वे पालिका अध्यक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे. बताते हैं कि गुटबाजी के कारण वे अध्यक्ष बनते बनते रह गए. रेखराम बंछोर वार्ड 3 से चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें हराने के लिए इसी वार्ड से सरोज पांडेय गुट के लोगों ने दूसरे वार्ड से सीट बदलकर गौशाला में गायों की मौत के आरोपी हरीश वर्मा को पार्षद का टिकट दे दिया. अधिकृत प्रत्याशी श्री बंछोर को हराने की पूरी तैयारी भी की गई लेकिन बंछोर के कमजोर जनाधार के कारण विरोधी सफल नहीं हो सके. किंतु जीत के बाद भी उन्हें दरकिनार कर सरोज गुट अपने चहेते ईश्वर ठाकुर को पालिका अध्यक्ष बनाने में सफल हो गया.

जनता और सीएम की उम्मीदों को करेंगे पूरा – नीरज

शहर की जनता जनार्दन द्वारा हमें मिली महती जिम्मेदारी का पूरी कर्मठता और ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा. हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता के साथ कांग्रेस और सरकार की अपेक्षाओं की कसौटी पर 24 कैरेट सोने की तरह खरा उतरना है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव के विकास के विश्वास पर खरा उतरने कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. पूरी निष्ठा और सक्रियता से नागरिकों के हितों और शहर के विकास के लिए काम करेंगे. साथ ही नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना और राज्य सरकार की योजनाओं को गति देना भी उनकी प्राथमिकता में है. सेक्टर-5 की तरह हर वार्ड के विकास के साथ चुनाव के पूर्व किये गये सभी वादों को पूरी संजीदगी से पूरा किया जाएगा.

नीरज पाल, महापौर नगर पालिक निगम भिलाई

भिलाई निकाय जैसे बड़े नगर निगम का सभापति निर्वाचित होना, गर्व के साथ एक जिम्मेदारी भरी चुनौती भी है. कांग्रेस और विधायक देवेन्द्र यादव द्वारा मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व देकर जो भरोसा जताया गया है, उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा. सामान्य तौर पर सभापति का मुख्य कार्य विधि अनुसार नगर निगम के सदन (सामान्य सभा) का सफलतापूर्वक संचालन करना होता है. मैं अपनी इस वैधानिक जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निर्वहन करने के साथ पूरी निष्पक्षता से सभी पार्षदों को अपनी बात रखने का भी अवसर प्रदान करूंगा.

गिरवर साहू, सभापति

भिलाई नगर पालिक निगम के नवनिर्वाचित एमआईसी मेम्बर

एकांश बंछोर
लोक कर्म विभाग

लक्ष्मीपति राजू
खाद्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग

साकेत चन्द्राकर
नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग

केशव चौबे
जल-कार्य विभाग

संदीप निरंकारी
सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग

सीजू एंथोनी
राजस्व विभाग

मन्नान गफ्फार खान
वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण विभाग

लालचंद वर्मा
अग्निशमन, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग

चंद्रशेखर गवई
गरीबी, उपशमन एवं सामाजिक कल्याण विभाग

मीरा बंजारे
महिला एवं बाल विकास विभाग

मालती ठाकुर
अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग

आदित्य सिंह
शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग

नेहा साहू
पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग

रीता सिंह गेरा
संस्कृति, पर्यटन, मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग

रिसाली में दरकता कांग्रेस का किला

रिसाली नगर निगम में कांग्रेस ने भले ही जीत दर्ज कर अपना महापौर बना लिया हो, पर वोट प्रतिशत और जीते गए वार्डों की संख्या कुछ और ही कहती हैं. पिछले निकाय चुनावों में कांग्रेस ने 13 में से 10 सीटें जीती थीं जबकि इस बार 40 में से केवल 21 सीटों पर ही उसने विजय प्राप्त की है. पिछले चुनावों में जहां उसे 20 हजार से अधिक वोट मिले थे वहीं इस बार उसे मात्र 13731 मतों से संतोष करना पड़ा है. यह बात और है कि कांग्रेस रिसाली निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल हुई है.

2015-16 के चुनाव में कांग्रेस ने 13 में से 10 सीटें जीती थीं और उसे 20 हजार से अधिक वोट मिले थे. भाजपा को इस चुनाव में केवल 2 सीटें मिली थीं जबकि एक प्रत्याशी निर्दलीय जीता था. फिर ऐसा क्या हुआ कि पुनर्गठन के बाद कांग्रेस का सीट और वोट प्रतिशत दोनों गिर गया जबकि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार है?

राजनीति की गोट और गणित को समझना आसान नहीं है. एक अच्छा माली कभी छोटे पौधों को धूप दिखाने के लिए बड़े पेड़ों को काटता-छांटता है तो कभी नए पौधों का पोषण सुनिश्चित करने के लिए खरपतवारों को उखाड़ता है. उद्देश्य बगीचे की समग्र सुन्दरता पर होती है. इस दृष्टि से देखें तो कांग्रेस के रणनीतिकार अपने प्रयास में सफल सिद्ध हुए हैं. पर जो हुआ है, वह दो साल बाद होने वाले विधानसभा के चुनावों की दृष्टि से चिंताजनक है.

2015-16 और 2021-22 के बीच काफी कुछ बदल गया है. 13 वार्डों का रिसाली निकाय अब 40 वार्डों का विशाल नगर निगम है. राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का रिसाली क्षेत्र से पुराना रिश्ता है.

दो की लड़ाई में तीसरे को लाभ

चुनावों की बात हो और इसमें जातिवाद का तड़का न हो तो बात अधूरी रह जाती है. रिसाली नगर निगम चुनाव के साथ भी ऐसा ही हुआ. ओबीसी महिला के लिए महापौर का पद आरक्षित था. पर यहां पर एक भी कुर्मी महिला को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी. इस बात को लेकर कुर्मी समाज में भारी नाराजगी देखी गई. तेली और कुर्मी खेमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही. टिकट वितरण पर भी इसका असर देखा गया. चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद स्थिति पर गहन मंथन किया गया. वर्चस्व की लड़ाई का पटाक्षेप करते हुए महापौर पद के लिए शशि सिन्हा का नाम प्रस्तावित कर दिया गया. सभापति पद के लिए केशव बंछोर को चुना गया. दोनों ही प्रत्याशियों ने 40 में से 27-27 वोट अपने नाम कर लिये.

शशि सिन्हा
महापौर

महिला सशक्तिकरण से महापौर की कुर्सी तक

रिसाली नगर निगम की प्रथम महापौर शशि सिन्हा यह पद पाकर अभिभूत हैं. पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जिस पर खरा उतरने की वे पूरी कोशिश करेंगी. वावा पाटणकर शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूर्व छात्रा शशि सिन्हा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वे लंबे समय से महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही हैं. वे सिन्हा समाज की जिला कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं.

शशि सिन्हा 2011 से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं. उनके पति अशोक कुमार सिन्हा भिलाई इस्पात संयंत्र में सीनियर क्रेन ऑपरेटर हैं. समाज के कहने पर ही उन्होंने पार्षद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. कांग्रेस का टिकट भी मिला और विजय भी हासिल हुई. इसके बाद जब महापौर पद के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया तो सहसा उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ. अंततः ग्राम लिमोरा, ब्लाक गुण्डरदेही, जिला बालोद की यह बेटी रिसाली नगर निगम की प्रथम महापौर बन गई.

श्रीमती सिन्हा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होंगी. महिला स्व-सहायता समूहों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी. निगम में शव वाहन की भी व्यवस्था की जाएगी. शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में चुस्ती लाने के प्रयास किये जाएंगे.

नगर निगम रिसाली के मेयर इन काउंसिल मेम्बर

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलालजी वोरा के समय से यह क्षेत्र वही संभालते रहे हैं. रिसाली नगर निगम के पुनर्गठन में उनकी बड़ी भूमिका रही है. उन्हें इस अंचल का राजनीतिक संरक्षक भी माना जाता है. पर निगम के पुनर्गठन के बाद यह तस्वीर बदल गई है. अब इसमें भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा इलाका शामिल हो गया है.

पिछले चुनाव में भाजपा यहां नेतृत्व विहीन थी. हालांकि भाजपा की कद्दावर नेता डॉ सरोज पाण्डेय का निवास यहीं है पर उनसे क्षेत्र के लोगों का सम्पर्क अब तक व्हाया दुर्ग ही है. पुनर्गठन के बाद जो इलाका रिसाली नगर निगम में शामिल हुआ है उसे भाजपा के एक अन्य कद्दावर नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व केबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है.

2015-16 और 2021-22 के चुनावों में दो बड़े अंतर हैं. पिछले चुनाव के दौरान प्रदेश में भाजपा का शासन था तो इस बार कांग्रेस का शासन है. शायद इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकार फीलगुड फैक्टर का शिकार हो गए. पांच वरिष्ठ पार्षदों का उसने टिकट काट दिया जबकि तीन और के लिए गड्ढे खोद दिये. पूर्व जोन अध्यक्ष भूपेन्द्र ठाकुर और मोनिका चंद्राकर जैसे वरिष्ठों को टिकट नहीं दी गई. जो प्रत्याशी हारे वे तीसरे चौथे नंबर पर रहे. उपेक्षा और भीतरघात के चलते राकेश मिश्रा, राजेन्द्र रजक, मुकुंद भाऊ जैसे वरिष्ठ लोगों को पराजय का मुंह देखना पड़ा. वोटों का प्रतिशत गिरने के लिए यह एक वजह ही काफी है.

भाजपा का बेहतर प्रदर्शन

पिछले चुनावों के दौरान भाजपा रिसाली में नेतृत्व विहीन थी जबकि इस बार इसमें भिलाई निगम का क्षेत्र भी शामिल हो गया है. भाजपा के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया और वोटों की संख्या बढ़ाने में कामयाब रहे. वार्डों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई तो भाजपा ने अपने पार्षदों की संख्या में छह गुना की वृद्धि दर्ज की.

चंद्रभान सिंह ठाकुर
जलकार्य विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग

गोविन्द चतुर्वेदी
स्वास्थ्य तथा विकित्सा एवं स्वच्छता विभाग

विलास राव बोरकर
राजस्व, बाजार तथा वाहन विभाग

अनूप डे
आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग

सनीर साहू
शिक्षा खेलकूद तथा युवा कल्याण विभाग

परमेश्वर कुमार
पुनर्वास तथा नगर नियोजन उद्यानिकी तथा संचार विभाग

सोनिया देवांगन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं विद्युत विभाग

ईश्वरी साहू
महिला बाल विकास एवं सामाज कल्याण तथा आजिविका विभाग

केशव बंछोर
सभापति

रिसाली नगर निगम को आदर्श निगम बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरुप पुरैना और जोरातराई जैसे दूरस्थ वार्डों के लिए वार्ड कार्यालय खोले जाएंगे. इससे समस्याओं का स्थानीय तौर पर ही निराकरण हो जाएगा और लोगों को निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. बेहतर कार्य संस्कृति विकसित की जाएगी. बैठक समय पर होंगे. सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा. पूर्ण पारदर्शिता रखने का प्रयास किया जाएगा. विकास के लिए धन कहीं भी आड़े नहीं आएगा.

भिलाई-चरोदा निगम भी फतह

दुर्ग जिले के 4 निकायों में से 3 निगमों में कांग्रेस की जीत हुई है. इनमें भिलाई-चरोदा निगम की जीत चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां अपनी फतह को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी भले ही अपनी ताल ठोके लेकिन इसकी जमीनी हकीकत के कुछ और ही सियासी निहितार्थ है.

भिलाई-चरोदा की जीत उस तरह कांग्रेस के लिए उपलब्धि नहीं है. जैसी कि भिलाई और रिसाली नगर निगम की जीत. भिलाई-चरोदा में लहराया कांग्रेस का परचम कई मायनों में पार्टी के लिए माइनस मार्किंग के चलते आत्ममंथन का विषय हो सकता है. इसका कारण यहां भले ही पार्टी ने पहली बार जीत हासिल कर ली है. लेकिन उसे बहुमत नहीं मिल पाना चिंता का सबब है. यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यह निगम क्षेत्र सीएम भूपेश बघेल का निवास और केबिनेट मंत्री गुरू रुद्र कुमार का विधानसभा क्षेत्र है. फिर राज्य में सत्तासीन होने के बाद भी पार्टी को निगम में जीत के लिए खासा पसीना बहाना पड़ गया. तमाम दावों के बावजूद पार्टी का कुल 40 में से मात्र 19 सीटें ही मिल पाईं. पाँच निर्दलीय पार्षदों के कांग्रेस प्रवेश के बाद ही कांग्रेस अपनी नगर सरकार बना सकी. यानी बार्डर से जीत के साथ वोट ऑफ परसेंटेज गिरना दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी है. राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि यदि समय रहते कांग्रेस ने अपने गिरते जनाधार को नहीं सुधारा तो आगामी चुनाव में भाजपा की बढ़त मुश्किल बढ़ा सकती है. निगम चुनाव में कांग्रेस के जनाधार कम होने की वजह जिम्मेदारों द्वारा टिकट वितरण में गंभीरता नहीं बरतना है. इस मामले में पार्टी सीएम व कद्दावर केबिनेट मंत्री का इलाका है किसी भी टिकट दे दो. वह जीत जाएगा मानसिकता के ओवर कांफिडेंट फोबिया का शिकार हो गई. इसी सियासी गफलत ने उसे जमीनी सच्चाई दिखा दी. फिर यहां हारते-हारते मिली जीत पार्टी को यह सोचने पर भी मजबूत करेगी कि पटरी के इस पार और पटरी के उस पार को लेकर खिंची जा रहे विभाजन रेखा को किस तरह वक्त रहते दुरुस्त किया जाए.

उल्लेखनीय है जनता और कार्यकर्ताओं में इस बीते को लेकर नाराजगी है कि पटरी के इस पार यानी उत्तर क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है. जबकि इसी क्षेत्र में सीएम का निवास है. ज्यादातर टिकट देने के साथ अब तक बने पालिका अध्यक्ष, महापौर और सभापति सभी पटरी पार यानी दक्षिण क्षेत्र के ही हैं. कुल मिलाकर मौजूदा सुस्त हाल को दुरूस्त नहीं किया गया तो निगम चुनाव की तरह विस चुनाव में भी पार्टी को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है.

अधिकांश नगर निगमों में बढ़ती निर्दलीयों की संख्या बार-बार इस ओर इशारा कर रही है कि निकाय चुनावों में जीतता वही है जिसकी वार्ड पर पकड़ होती है और जनहितैषी छवि होती है. कांग्रेस के रणनीतिकारों को इस बात को समझने के साथ ही इस पर अमल करने की भी जरूरत है. मेरा आदमी-तेरा आदमी जैसे मसलों को इन निकाय चुनावों से दूर ही रखना चाहिए. दो-दो कद्दावर नेताओं के होते हुए भी यहां

कांग्रेस बिखरी बिखरी सी रही. खेमेबाजी सिर चढ़कर बोलता रहा. लोगों ने केवल निर्दलीय प्रत्याशियों की मदद की बल्कि पार्टी प्रत्याशी को हराने के लिए भी लामबंदी की. चिंता का विषय यह है कि ऐसा होने दिया गया. दोनों बंगलों के बीच तालमेल नहीं होने के कारण चुनाव सामग्री और संसाधनों का वितरण भी प्रभावित हुआ. इससे चाटुकारों को अवसर मिला और वे बंगलों में बैठकर अपने आकाओं को झूठी ग्राउंड रिपोर्ट देते रहे.

रणनीति की बात करें तो कांग्रेस ने कई मोर्चों पर गलतियां कीं. मुख्यमंत्री तो अपनी जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं पर केबिनेट मंत्री भी चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से रायपुर के होकर रह गए. यहां तक कि जिलाध्यक्ष भी पूरे चुनाव के दौरान अपने ही वार्ड में सिमटे रहे. इसके कारण पूरे चुनाव के दौरान तालमेल का जबर्दस्त अभाव बना रहा और नतीजे भी प्रभावित हुए.

ऐसे हो सकता है डैमेज कंट्रोल

भिलाई-3 चरौदा नगर निगम का बड़ा हिस्सा पटरियों के उत्तर की तरफ का है जिसमें अहिवारा विधानसभा के एक बड़ा हिस्सा आता है. इस इलाके से 29 पार्षद चुने जाते हैं. पर अब तक का इतिहास इस क्षेत्र की उपेक्षा का ही रहा है. महापौर या सभापति अब तक पटरियों के दक्षिण से ही चुने जाते रहे हैं. इस बार भी स्थिति यही बनी हुई है. यदि इस असंतुलन को दूर नहीं किया गया तो अहिवारा विधानसभा वाला अंचल राजनीतिक असंतोष का टापू बनकर उभर सकता है. लगभग तीन चौथाई सीटों वाले इस इलाके को आखिर कब तक छला जाएगा?

भिलाई-3 चरोदा बनेगा आदर्श नगर निगम

निर्मल कोसरे
महापौर

भिलाई-3 चरोदा नगर निगम को आदर्श नगर निगम बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्र को ग्रीन, यलो तथा रेड जोन में बांटकर कार्ययोजना बनाई जा रही है. इसी तरह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की क्षमता को दोगुना किया जा रहा है. मिनी स्टेडियम को विस्तार देने के साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर को व्यवस्थित करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. निगम में सिटीजन चार्टर का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाएगा. समयसीमा में कार्य न होने पर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही जनऔषधि केन्द्रों की भी मानिटरिंग की जाएगी. जनसहयोग से स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. सब मिलकर कोशिश करेंगे तो भिलाई-3 चरोदा की तस्वीर जल्द ही बदल जाएगी. एक अभिनव योजना के तहत महापुरुषों के तैलचित्रों को उनके जन्मदिन पर नगर निगम के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसमें क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों के तैलचित्र शामिल होंगे. इस योजना का प्रारंभ 26 जनवरी को किया जाएगा.

“निगम में जनता का काम प्राथमिकता से पूरा होगा. यहां पर जनता के घूमने और घुमाने वाला काम नहीं होगा. निश्चित समयावधि में सारे काम होंगे. दूसरे काम प्रभावित न हो इसका ध्यान रखा जाएगा. बिल्डिंग परमिशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास जैसे काम समयावधि में पूरे होंगे. चूंकि भिलाई-3 चरोदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास क्षेत्र है और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार की कर्मभूमि है. अत: विकास भी उन्हीं की परिकल्पनाओं के अनुरूप होगा.

कृष्णा चन्द्राकर
सभापति, नगर निगम भिलाई-चरोदा

भिलाई-चरोदा नगर पालिक निगम के नवनिर्वाचित एमआईसी मेम्बर

संतोष तिवारी
आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग

एम. जानी
जल कार्य विभाग

देवकुमारी भलावी
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग

मोहन साहू
राजस्व तथा बाजार विभाग

दीप्ति वर्मा
शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग

मनोज कुमार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति

ईश्वर साहू
पुनर्वास तथा नियोजन विभाग

संतोषी निषाद
विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग

बीरगांव नगर निगम में भी कांग्रेस

बीरगांव नगर निगम के चुनाव में 40 वार्डों वाले निगम के 19 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है. भाजपा के हिस्से में केवल 10 सीटें आई हैं. 5 सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार जीतें हैं तो 6 सीटों पर निर्दलीय जीतकर आए हैं. बीरगांव चुनाव 2015 की अपेक्षा कांग्रेस को दो और भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ है. बीते साल कांगेस के पास 21 सीटें थी और बीजेपी के पास 13 सीट रही. बीते साल भी 6 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे. जकांछ (जे) पहली बार बीरगांव नगर निगम चुनाव में उतरी और उसने 5 सीटें हांसिल की. जकांछ ने दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाया. कांग्रेस और भाजपा के बागियों ने भी नुकसान पहुंचाया.

कांग्रेस के लिए यह बड़ा जनाधार है. जनता ने भाजपा के साम्प्रदायिक एजेंडे को नकार दिया है. यद्यपि भाजपा ने यहां कई बार साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयम का परिचय दिया. नतीजतन बीरगांव नगर निगम के निर्वाचित महापौर कोष्टा समाज के नंदलाल देवांगन और केंवट समाज के सभापति कृपाराम निषाद चुने गए हैं. यहां के मतदान का दिलचस्प पहलू यह है कि मतदान के दिन भाजपा के दो विधायक अजय चन्द्राकर और नारायण चंदेल मोहल्ले में ही कुर्सी डालकर बैठ गए. मतदान स्थल से बाहर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मोर्चा संभाल रखा था.

नंदलाल देवांगन
महापौर

औद्योगिक क्षेत्र है बीरगांव. यहां पर लोगों की बड़ी समस्या रोजगार, वायु प्रदूषण और शुद्धपेयजल की है. जल आवर्धन योजना के तहत गर्मी मास के पहले तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है. यहां के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे. निर्माणाधीन कॉलेज भवन का काम अतिशीघ्र पूरा कराएंगे, ताकि नए सत्र से छात्रों की पढ़ाई शुरू हो सके. विकास कार्यों में और तेजी लाने की हमारी कोशिश होगी.

कृपाराम निषाद
सभापति

नगर निगम के सदन में व्यवस्था बनाना हमारी जवाबदेही है. इस महती जिम्मेदारी को गंभीरता से संभालते हुए जनभावना के अनुरूप विकास से जुड़ी जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा. चूंकि बीरगांव निगम का गठन आसपास के 6 गांवों को मिलाकर किया गया है. इसलिए हमारी प्राथमिकता समूचे ग्राम्य क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पार्षदों को प्रेरित करना है.

उबारन दास बंजारे
आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग

इकराम अहमद
जल कार्य विभाग

मोहम्मद रियाज
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग

बसंत सेन
राजस्व तथा बाजार विभाग

भारती नंदू चंद्राकर
शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग

सरोजबाई कुर्रे
खाद्य, नागरिक आपूर्ति

ओमप्रकाश साहू
पुनर्वास तथा नियोजन विभाग

संतोष कुमार साहू
विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग

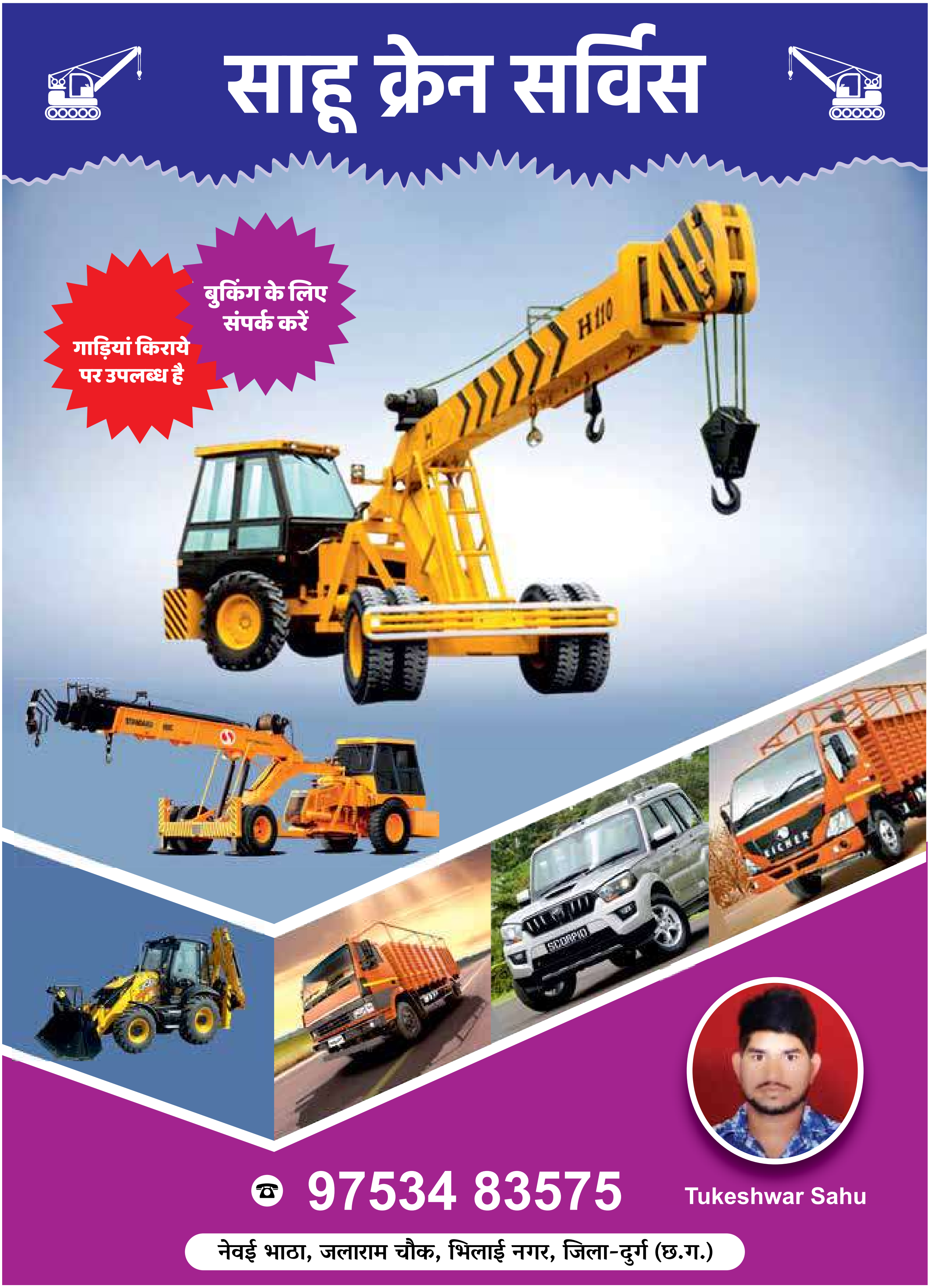
साहू क्रेन सर्विस
बुकिंग के लिए संपर्क करें
गाड़ियां किराये पर उपलब्ध है
H 110
97534 83575
Tukeshwar Sahu
नेवई भाठा, जलाराम चौक, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

लाभ की खेती मखाना

■ बाजार में "दाऊ जी" मखाने की धूम ■ वैकल्पिक और नगदी खेती का एक नया उदाहरण

कोरोनाकाल में जहां लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है. लोग भयभीत और डरे हुए हैं. इसी भय की वजह से कई लोगों की मौतें भी हुई हैं. ऐसे समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मखाना एक संजीवनी की तरह साबित हुई है. चिकित्सकों ने माना है कि मखाने में प्रोटीन, विटामिन और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है. मखाने के सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. सरकार ने जब नगदी फसल और फसल चक्र परिवर्तन की ओर किसानों का ध्यान आकर्षित किया है. मखाना एक वैकल्पिक औषधि और सुपर फूड के रूप में सामने आयी है.

रायपुर जिले के अंतर्गत आरंग ब्लॉक के ग्राम लिंगाडीह निवासी प्रगतिशील किसान गजेंद्र चंद्राकर ने अपनी 30 एकड़ जमीन में मखाने की खेती कर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने "मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केन्द्र" का पिछले दिनों वर्चुअल उद्घाटन कर फसल चक्र परिवर्तन के लिए प्रदेश के किसानों को आह्वान किया है. इस अवसर पर उन्होंने लिंगाडीह के ओजस कृषि फार्म में उत्पादित मखाने की "दाऊ जी" ब्रांड नाम से लांचिंग की. गजेन्द्र चंद्राकर एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं. उनका कहना है कि मखाने की खेती से किसानों की आमदनी दो से तीन गुणा बढ़ जाएगी वहीं जोखिम भी अन्य नगदी फसलों की तुलना में कम हो जाएगी.

यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस कृषि वैज्ञानिक ने नई सोच एवं नए नजरिए के साथ मखाने की खेती अपने 30 एकड़ खेत में शुरू की. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध गजेन्द्र चन्द्राकर इसके पीछे भी किसानों को फसल चक्र परिवर्तन में फसल लेने की तकनीक बताते हैं. वे उन्हें यह भी समझाते हैं कि मखाने की जरूरत क्या है और क्यों है? इससे धान की खेती करने वाले किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि करने के लिए मखाना की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इससे आसपास के गांव में भी मखाने की खेती करने की प्रेरणा मिलती है.

राजधानी रायपुर से 35 किलोमीटर दूर स्थित आरंग से 6 किमी दूर मखाने की खेती कर रहे लिंगाडीह गांव के प्रगतिशील किसान गजेन्द्र चन्द्राकर ने अपने 30 एकड़ खेत में मखाने की खेती से किसानों को भी अपार फायदा हो रहा है. यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि यदि कृषि वैज्ञानिक ने नई सोच और नए नजरिए के साथ मखाने की खेती शुरू क्यों की? वे प्रतिदिन रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाने आते हैं तो इसके पीछे भी किसानों को फसल चक्र परिवर्तन में फसल लेने की जरूरत बताते हैं. इससे धान की खेती करने वाले किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि करने के लिए मखाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इससे आसपास के जिलों में भी मखाने की खेती करने की प्रेरणा मिलती है.

प्रति एकड़ एक लाख रुपये का मुनाफा

धान की तुलना में खेतों में दो या तीन

फीट तक पानी भरकर मखाने की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है. मखाने की खेती में 6 महीने का समय लगता है. एक एकड़ में करीब 10 से 05 क्विंटल का उत्पादन होता है. इसके बीज की कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो होती है. इस लिहाज से एक एकड़ में 80 हजार से एक लाख रुपए तक 6 महीने में आराम से कमाई हो सकती है.

हाईटेक हार्टिकल्चर पर काम

वैकल्पिक खेती के लिए छत्तीसगढ़ में हाईटेक हार्टिकल्चर पर भ् काम चल रहा है. धान के बाद यानी 6 महीने से 8 महीने तक नमी रहती है. ऐसे में कोई प्राफिटेबल क्रॉप सब्सिट्यूट के रूप में अल्टरनेटिव फार्मिंग के रूप मे नहीं उपजाया जा सकता था. यहां पर 25 से 30 एकड़ वॉटर एरिया में मखाना की खेती की जा रही है. ये फसल न्यूट्रीशन रिच फूड है. इसकी विश्व स्तर पर अच्छी मांग है. सबसे बड़ी बात है कि धान के मुकाबले इसको न तो ज्यादा बारिश से नुकसान है और न ही जानवरों से, क्योंकि ये पानी के भीतर तालाबनुमा पोखर में होता है. इसलिए इस फसल को धान की तरह चोरों से भी कोई भय नहीं है.

मखाना एक नगदी फसल है

मखाना निम्फियेसी परिवार का एक जलीय पौधा है. इसे साधारणतया गोरगोन नट या फॉक्स नट कहते हैं. मखाना को

“काला हीरा” भी कहा जाता है. यह उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है. इसके सही विकास एवं बढ़वार के लिए 200 डिग्री से 350 डिग्री तापमान, सापेक्षित आद्रर्ता 50 फीसदी से 90 फीसदी तथा 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का होना अतिआवश्यक है. यह एक नगदी (सूखा फसल) है. यह पॉण्ड मखाना या लावा के रूप में बाजार में उपलब्ध है.

प्रति एकड़ सवा लाख रुपये तक की उपज

छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसान और कृषि वैज्ञानिक गजेन्द्र चन्द्राकर कहते हैं कि मखाने की खेती दिसबंर-जनवरी और जुलाई-अगस्त में कर सकते हैं. मखाने का बीज तालाब में डालने पर 60 दिनों बाद फल आता है. एक एकड़ मे 15 से 25 हजार रुपए तक का खर्च आता है. प्रति एकड़ 10-12 क्विंटल उत्पादन होता है. इसकी कीमत एक से सवा लाख रुपए होती है. धान की खेती की तरह ही गतई कर 4 हजार पौधा प्रति एकड़ रोपाई करते हैं. खेत में 4 इंच से एक फीट तक पानी रख सकते हैं.

इन राज्यों में मखाने की खेती

देश में मखाने का प्रसार पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वी ओड़िसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश में हुआ है, जबकि इसकी व्यावसायिक खेती उत्तरी बिहार, मणिपुर, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों एवं मध्यप्रदेश तक सीमित है.

डॉ. गजेन्द्र चन्द्राकर का 35 एकड़ कृषि भूमि जहां वे मखाना की खेती करते हैं...

छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुई वाणिज्यिक खेती

छत्तीसगढ़ में भी इसकी व्यावसायिक खेती प्रारंभ हो चुकी है. किसानों को मखाने की खेती हेतु बीज से बाजार तक की सुविधाएं मुहैय्याकराई जा रही है. अब छत्तीसगढ़ में भी वृहद स्तर पर प्रथम बार ग्राम लिंगाडीह आरंग ब्लॉक में इसकी व्यावसायिक खेती की जा रही है. नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं भ्रमण सेवाएं दी जा रही है.

प्रोटीन का अच्छा स्रोत

भारत और चीन के प्राचीन साहित्य में मखाना के औषधीय गुणों की चर्चा विस्तार से की गई है. इसका उपयोग पुराने पेचिस, योनि स्राव (श्वेत प्रदर), नामर्दी, समयपूर्व और अनैच्छिक स्खलन, स्वप्नदोष और बार-बार पेशाब से संबंधित वृक्क की कमजोरी के इलाज में किया जाता है.

डाईटीशियन डॉ. सारिका श्रीवास्तव कहती हैं कि मखाना के बीज का उपयोग बहुत से आयुर्वेदिक औषधि के निर्माण में किया जाता है. मखाना वात और पित्त दोष को घटाता है, जिसका उपयोग नपुंसकता (नामर्दी) के निवारण में किया जाता है. गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह फायदेमंद है. मखाने का सेवन किडनी और दिल की सेहत के लिए भी लाभप्रद है.

डायबिटीज के रोगी भी इसका सेवन

कर सकते हैं. मखाने में कैल्शियम भरपूर होता है इसलिए जोड़ों के दर्द, विशेषकर अर्थराइटिस के मरीजों के लिए यह लाभप्रद औषधि है. मखाने के सेवन से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है. इसके नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है. मखाने मे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैट, मिनरल, फॉस्फोरस आदि पोषण तत्तव होते हैं. पुरुषों के लिए यह बेहद फायदेमंद माने गए हैं. यह महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करता है.

प्रसंस्करण में उच्च तम मानकों का पालन

ओजस फॉर्म लिंगाडी में मखाना प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किया गया है. बाजार की मांग के अनुरूप सादे, रोस्टेड, फ्लेवर्ड मखाना यहां प्रसंस्करित किए जाते हैं. कृषि उद्यमियों की टीम मखाने की खेती से लेकर प्रसंस्करण तक वैज्ञानिक पद्धति अपनाती है. निरीक्षण करती है. और उच्चतम मानकों का ध्यान रखती है, जो इसके टैगलाईन है. साइंटिफिकली मानिटर्ड को यथार्थ बनाती है.

उत्कृष्ट पैकेजिंग

फार्म में उत्कृष्ट पैकेजिंग की व्यवस्था भी है. पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बायोडिग्रेडेबल व रिसायकलबल प्लास्टिक में ही यहां पैकेजिंग की जाती है. इसका नाम गजेन्द्र चन्द्राकर ने अपने पिता की स्मृति में “दाऊ जी” रखा है. ऑन लाईन, ऑफ लाईन व डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाते हैं.

वार्ड क्रमांक 08 से
पार्षद पद पर
निर्वाचित होने एवं
महापौर परिषद के सदस्य
बनाए जाने पर
क्षेत्र की जनता का
हार्दिक
आभार
चन्द्रभान सिंह ठाकुर
एमआईसी सदस्य (कार्य विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग)
नगर पालिक निगम रिसाली, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम

- हर साल ड्योढ़ा हो रही मामलों की संख्या
- बढ़ रहा अनसुलझे मामलों का ग्राफ
- छह राज्यों की पुलिस साझा कर रही विशेषज्ञता

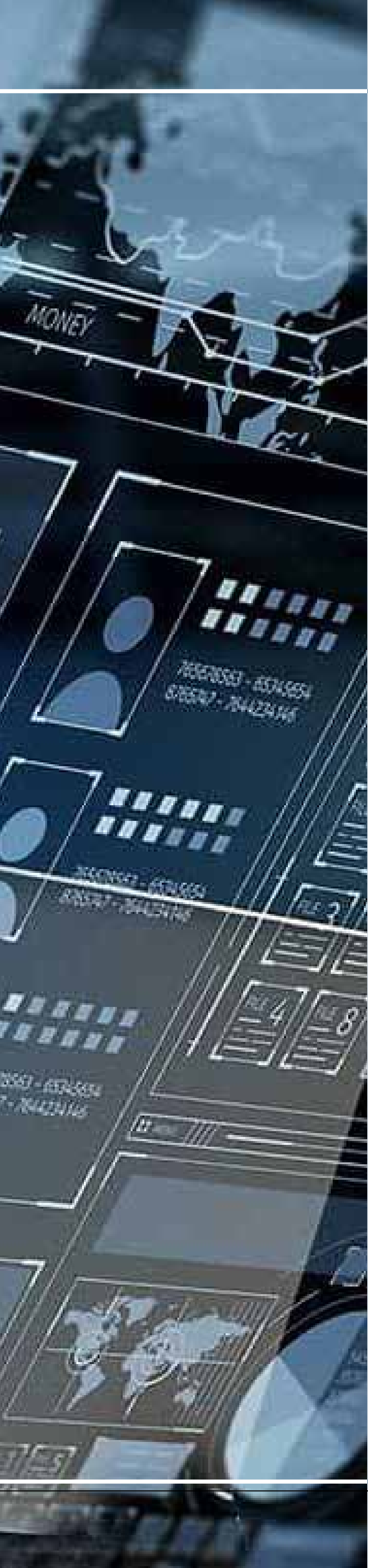

जामतारा के बाद छत्तीसगढ़ साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है. प्रदेश पुलिस के साथ नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है. साइबर अपराध के मामले में फिलहाल छत्तीसगढ़ 14वें पायदान पर है. छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 में 2016 के मुकाबले साइबर अपराधों में डेढ़ गुना की वृद्धि हुई. इसके बाद से हर साल दर्ज मामलों का कमोबेश यही अनुपात बना रहा. चिंता की बात यह है कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग लालच में आकर सायबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर असावधानी अनेक युवाओं का जीवन तबाह कर चुकी है.

2017 में देशभर में साइबर अपराध की कुल 21796 मामले दर्ज किये गए. इनमें से 171 मामले छत्तीसगढ़ के थे. इससे पहले 2015 से 2017 के बीच 45705 मामले दर्ज किये गये थे. छत्तीसगढ़ में तमाम कोशिशों के बाद भी न केवल साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं बल्कि अनसुलझे मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. वर्ष 2018 में साइबर क्राइम के कुल 348 मामले दर्ज किए गए जिनमें से 124 मामलों को सुलझा लिया गया तथा 18,71,146 रुपए का रिफंड करवाया गया. इसी तरह 2019 में 548 मामले दर्ज हुए जिनमें से 155 मामले सुलझा लिये गये और 38,00,836 रुपए का रिफंड संभव हुआ. इसी तरह 2020 में 660 मामले दर्ज किए गए जिनमें से केवल 129 मामले ही सुलझाए जा सके और 22,525,939 रुपए का रिफंड करवाया जा सका. 2021 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) तक 320 मामले दर्ज किये जा सके थे जिनमें से 101 मामलों का निपटारा करते हुए 12,34,000 रुपए का रिफंड करवाया गया.

पुलिस कर रही तैयारी :

सायबर अपराधों की तेजी से बढ़ते ग्राफ के खिलाफ पुलिस खुद को तैयार कर रही है. सायबर एक्सपर्ट्स की मदद लेने के साथ ही पुलिस बल के अधिकारियों को भी विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है. माना जाता है कि त्वरित शिकायत और पुलिस के रिस्पांस टाइम में सुधार से ही इन आंकड़ों को बदला जा सकता है. साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए छह राज्यों की पुलिस ने इसी साल अक्टूबर में बैठक की जिसमें सभी राज्यों के अनुभवी अधिकारियों ने स्टेकहोल्डर्स, बैंक अधिकारी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ बैठकर जानकारी साझा की.

पुलिस ने कहा है कि अगर कोई साइबर अपराध का शिकार होता है तो तत्काल शिकायत दर्ज करवाए. सही समय पर शिकायत मिलने पर साइबर सेल तत्काल उन तक पहुंच रही है. सैकड़ों लोगों के पैसे वापस करवा चुकी है. बैंक के माध्यम से पुलिस ने पैसे होल्ड करवा दिए हैं. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतें ऑनलाइन की जा सकती है. हेल्पलाइन नंबर 155260 में फोन कर घटना के 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा शिकायत दर्ज करने के लिए https://cybercrime.gov.in/ टाइप कर साइट में विजिट किया जा सकता है. ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक कुल 978 मामले दर्ज किये गये जिसमें से 10,17,375 का भुगतान होल्ड पर रखा गया और 3,34,531 रुपयों का रिफंड करवाया गया. इसी तरह ऑपलाइन मिली शिकायतों की संख्या 620 थी जिसमें 20,82,911 रुपए का रिफंड करवाया गया. ऑनलाइन ऑर ऑफलाइन शिकायतों का कुल रिफंड 31,00,286 रुपए का रहा.

साइबर अपराध के प्रकार

साइबर क्राइम को मोटे तौर पर पांच श्रेणियों में रखा जा सकता है. हैकिंग- किसी के कम्प्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकार प्रवेश कर गड़बड़ी करना, साइबर स्टॉकिंग- इंटरनेट के किसी यूजर को संदेशों, प्रस्तावों या धमकियों से परेशान करना, DDos अटैक – किसी यूजर की साइट को डाउन कर उसपर काबू करना, पहचान की चोरी – यूजर के नाम और महत्वपूर्ण डाटा को हासिल करना, चाइल्ड एब्यूज और चाइल्ड पोर्नोग्राफी. इसके लिए स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग (जानकारी समाप्त करना), वायरस फैलाना, सॉफ्टवेयर पाइरेसी, फर्जी बैंक कॉल करना, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना, साइबर बुलिंग (सोशल मीडिया में कमेंट और धमकी देना), जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, फेर बदल करना, बाहरी नुकसान पहुंचाना आदि शामिल है.

साइबर अपराध की रोकथाम

सरकार ने सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 लागू किया है. अपराध की प्रकृति के आधार पर भारतीय दंड संहिता, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है. कुछ मामलों में आईटी नियम 2011 भी लागू होते हैं.

बचने के उपाय

कंप्यूटर, मोबाइल व सोशल मीडिया के लिए मजबूत पासवर्ड बनाएं. 8 वर्ड का पासवर्ड बनाए. पासवर्ड में अपर व लोअर केस, संख्या व स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग करें. नवीनतम एंटी वायरस एवं फायर बॉल का प्रयोग करें. केवल विश्वसनीय वेबसाइट से ही नि:शुल्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें.

महत्वपूर्ण डाटा का नियमित बैकअप जरूर रखें. मोबाइल का 15 अंकों का ईएमईआई नंबर अपने पास सुरक्षित रखें. मोबाइल को पैटर्न लॉक/फिंगर प्रिंट लॉक पासवर्ड युक्त रखें. पैसे निकासी के बाद की-बोर्ड का कैंसिल बटन जरूर दबाएं. व्हाटसएप के प्राइवेसी सेटिंग में अपनी प्रोफाइल पिक्चर को रिस्ट्रिक्टेड रखें.

यह कभी न करें

- काम पूरा होते ही फाइल शेयरिंग ऑप्शन बंद करें
- अपने कम्प्यूटर या मोबाइल को असुरक्षित न छोड़ें
- पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करें
- अनजान डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ न जोड़ें
- उपयोग के बाद मोबाइल एप्स को बंद कर दें
- समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें
- कार्ड स्वाइप मशीन का उपयोग स्वयं करें
- व्यक्तिगत फोटो या जानकारी सोशल साइट पर साझा न करें.

साइबर अपराध से जुड़ी धाराएं

सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत, किसी की गोपनीयता भंग करने के लिए कई धाराओं के तहत आढ़तियों और साइबर अपराधियों पर मामला दर्ज किया जा सकता है. अधिकांश धाराओं में तीन साल तक की कैद अथवा एक लाख रुपए तक जुर्माना यो दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं.

धारा 67	: इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित है.
धारा 66 A	: संचार सेवा के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजना.
धारा 66 B	: चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण.
धारा 66 C	: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या अन्य पहचान दस्तावेज़ की चोरी करना.
धारा 66 D	: संचार उपकरण के उपयोग द्वारा धोखा देना.
धारा 66 E	: गोपनीयता का उल्लंघन –गोपनीय जानकारियों को सहमति के बिना प्रकाशित या प्रसारित करना.
धारा 66 F	: साइबर आतंकवाद – राष्ट्र की एकता, अखंडता, या सुरक्षा को खतरे में डालने और कंप्यूटर संसाधन तक पहुंचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को इनकार करना या प्राधिकरण के बिना कंप्यूटर संसाधन में घुसने या प्रवेश करने का प्रयास करने का इरादा रखना.
धारा 72	: गोपनीयता और गोपनीयता भंग करने के लिए सजा.
धारा 72 A	: कानूनन कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सूचना का खुलासा करने के लिए सजा.
धारा 441	: आईपीसी: यह धारा आपराधिक अत्याचार से संबंधित है.
धारा 354D	: यह खंड गतिरोध से संबंधित है. यह स्टाकर को एक पुरुष के रूप में परिभाषित करता है जो एक महिला का पीछा करता है और उस महिला से संपर्क करने की कोशिश करता है, डिजिटल मीडिया का उपयोग करते समय महिला द्वारा की गई हर गतिविधि पर नज़र रखता है.

साइबर अपराध से जुड़े कानूनी उपचार

कानून :
- आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43 (ए), धारा 66
- आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कार्रवाई

सजा : अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल और/या पांच लाख रुपये तक जुर्माना.

डेटा की चोरी

निजी या गोपनीय डेटा (सूचनाओं) की चोरी, अपने नियंत्रण की सूचनाओं या डेटा का अनाधिकृत उपयोग, निजी स्वार्थ में डेटा कम्प्रोमाइज आदि इसके दायरे में आते हैं.

कानून :
- आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43 (बी), धारा 66 (ई), 67 (सी)
- आईपीसी की धारा 379, 405, 420

- कॉपीराइट कानून

सजा : अपराध की गंभीरता के हिसाब से तीन साल तक की जेल और/या दो लाख रुपये तक जुर्माना.

वायरस-स्पाईवेयर फैलाना

वायरस बनाने वाले अपराधियों की पूरी इंडस्ट्री है जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है. आम इंटरनेट यूजर भी कानून के दायरे में आ सकते हैं, अगर उनकी लापरवाही से किसी के सिस्टम में खतरनाक वायरस पहुंच जाए और बड़ा नुकसान कर दे.

कानून :
- आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43 (सी), धारा 66
- आईपीसी की धारा 268
- साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66 (एफ) भी लागू (गैर-जमानती).

सजा : साइबर-वॉर और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद. दूसरे मामलों में तीन साल तक की जेल और/या जुर्माना.

पहचान की चोरी

दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए शॉपिंग, धन आहरण/निकासी करना आइडेंटिटी थेफ्ट (पहचान की चोरी) के दायरे में आता है.

कानून :
- आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43, 66 (सी)
- आईपीसी की धारा 419 का इस्तेमाल मुमकिन

सजा: तीन साल तक की जेल और/या एक लाख रुपये तक जुर्माना.

ई-मेल स्पूफिंग और फ्रॉड

किसी दूसरे शख्स के ई-मेल पते का इस्तेमाल करते हुए गलत मकसद से दूसरों को ई-मेल भेजना इसके तहत आता है. हैकिंग, फिशिंग, स्पैम और वायरस-स्पाईवेयर फैलाने के लिए इस तरह के फ्रॉड का इस्तेमाल ज्यादा होता है. इनका मकसद ई-मेल पाने वाले को धोखा देकर उसकी गोपनीय जानकारियां हासिल कर लेना होता है. ऐसी जानकारियों में बैंक खाता नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ई-कॉमर्स साइट का पासवर्ड वगैरह आ सकते हैं.

कानून :
- आईटी कानून 2000 की धारा 77 बी
- आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 66 डी
- आईपीसी की धारा 417, 419, 420 और 465.

सजा : तीन साल तक की जेल और/या जुर्माना.

पोर्नोग्राफी

यौन कृत्यों और नग्नता से जुड़े फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और अन्य सामग्री का प्रकाशन, प्रसारण आदि इसके दायरे में आते हैं. एमएमएस बनाना, उसे वायरल करना या उसे आगे शेयर करना अपराध है. हालांकि ऐसी सामग्री को देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं है. कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, धर्म आदि से जुड़े कामों के लिए जनहित में तैयार की गई उचित सामग्री अवैध नहीं मानी जाती.

कानून :
- आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए)
- आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509

सजा : पहली गलती पर पांच साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना. दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा सात साल हो जाती है.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी

पोर्न कंटेन्ट में यदि बच्चे दिखाई दे रहे हों या उनका उल्लेख हो तो इसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं. ऐसे मामलों में कानून बेहद सख्त है. ऐसी सामग्री को सर्च करना, उन्हें डाउनलोड करना, स्टोर करना गंभीर अपराध है. बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रेकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसके तहत आते हैं. यहां बच्चों से मतलब है - 18 साल से कम उम्र के लोग.

कानून :
- आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 67 (बी), आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509

सजा : पहले अपराध पर पांच साल की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना. दूसरे अपराध पर सात साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना.

साइबर बुलीइंग

सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ई-मेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले जब-तब सामने आते रहते हैं. डिजिटल जरिए से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर क्राइम के दायरे में आता है. किसी के खिलाफ अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना या बदनाम करना.

कानून :
- आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 66 (ए)

सजा : तीन साल तक की जेल और/या जुर्माना

बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का उल्लंघन

वेब पर मौजूद दूसरों की सामग्री को चुराकर अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करने और प्रकाशित करने के मामलों पर भारतीय साइबर कानूनों में अलग से प्रावधान नहीं हैं, लेकिन पारंपरिक कानूनों के तहत कार्रवाई की मुनासिब व्यवस्था है. किताबें, लेख, विडियो, चित्र, ऑडियो, लोगो और दूसरे क्रिएटिव मटीरियल को बिना इजाजत इस्तेमाल करना अनैतिक तो है ही, अवैध भी है. साथ ही सॉफ्टवेयर की पाइरेसी, ट्रेडमार्क का उल्लंघन, कंप्यूटर सोर्स कोड की चोरी और पेटेंट का उल्लंघन भी इस जुर्म के दायरे में आता है.

कानून :
- कॉपीराइट कानून 1957 की धारा 14, 63 बी

सजा : सात दिन से तीन साल तक की जेल और/या 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये तक का जुर्माना.

शिक्षित बनो। संगठित रहो। संघर्ष करो।।

महापरिनिर्वाण पर विनम्र श्रद्धांजलि

भारत रत्न : बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

बी.ए., एम.ए.-समाज शास्त्र, इतिहास, दर्शन नृविज्ञान, राजनीति एवं अर्थशास्त्र, पी.एच.डी., एम.एस-सी., बार एट लॉ, डी.लिट, एल.एल.डी., डी.एस-सी.

"मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है. यह कारवां आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूं. तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदा आगे ही बढ़ते रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों न आये. यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सकें, तो इसे यहीं छोड़ दे, पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दें. आप लोगों को मेरा यही अंतिम संदेश है."

डॉ. अद्दंकि रंजित ओफीर
संस्थापक अध्यक्ष

सत्यप्रकाश भारती
प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़

स्वामी नादलू
प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

पूनम बावनकर
प्रदेश महासचिव

डॉ. शोभा मिंज
प्रदेश कोषाध्यक्ष

विनीत

सिलास नवगिरे (प्रदेश उपाध्यक्ष), उमा वाडेकर (प्रदेश अध्यक्ष, महिला विंग), गीता सिंह, सुभाष पॉल (प्रदेश सचिव), सुरेन्द्र सिंह (प्रदेश कार्यकारिणी), श्रीमती उमा पाण्डेय (जिलाध्यक्ष, दुर्ग), संदीप खोबागड़े (जिलाध्यक्ष, यूथ विंग), डॉ. किशोर वर्मा, श्याम वर्मा, राजनारायण जांगड़े (राजनांदगांव), बसंत देवांगन (उतई) एवं समस्त कार्यकर्तागण छत्तीसगढ़

इंडिया प्रजा बंधु पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चिल्हाटी, पं. क्र.-03
प्रदेशवासियों को नववर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएं...
2022
HAPPY NEW YEAR
के. के. चंद्रवंशी
प्राधिकृत अधिकारी
योगेश कुमार त्रिपुरे
समिति प्रबंधक

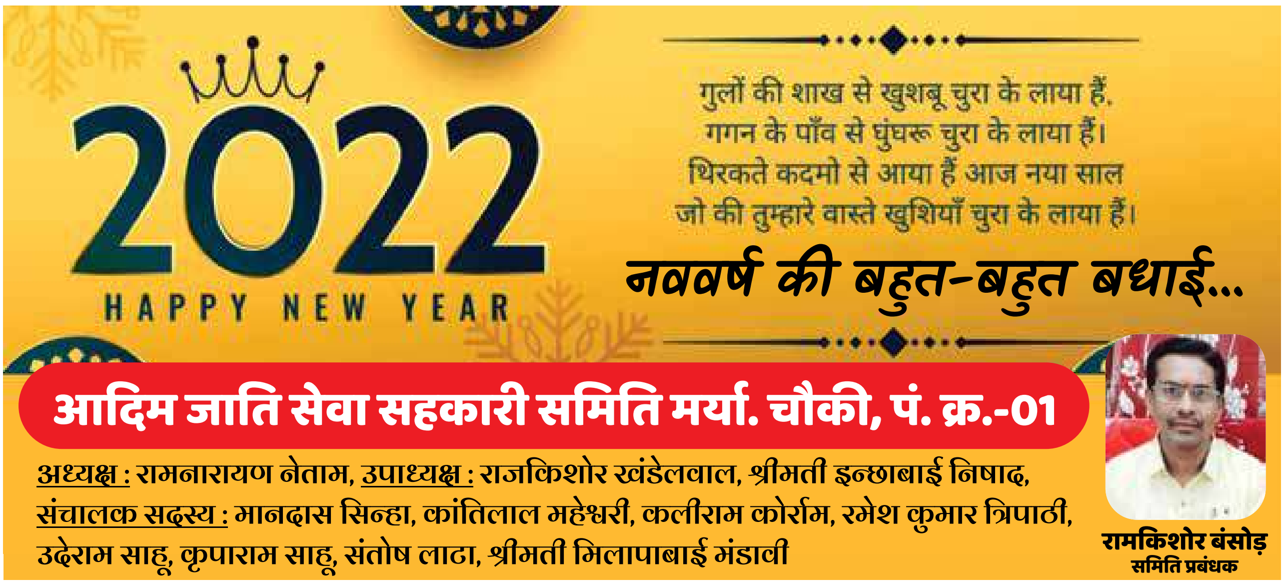
2022
HAPPY NEW YEAR
गुलों की शाख से खुशबू चुरा के लाया हैं,
गगन के पाँव से घुंघरू चुरा के लाया हैं।
थिरकते कदमो से आया हैं आज नया साल
जो की तुम्हारे वास्ते खुशियाँ चुरा के लाया हैं।
नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई...
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. चौकी, पं. क्र.-01
अध्यक्ष : रामनारायण नेताम, उपाध्यक्ष : राजकिशोर खंडेलवाल, श्रीमती इन्छाबाई निषाद,
संचालक सदस्य : मानदास सिन्हा, कांतिलाल महेश्वरी, कलीराम कोर्राम, रमेश कुमार त्रिपाठी,
उदेराम साहू, कृपाराम साहू, संतोष लाटा, श्रीमती मिलापाबाई मंडावी
रामकिशोर बंसोड़
समिति प्रबंधक

नववर्ष
की हार्दिक शुभकामनाएं
आदिम जाति सेवा सह. समिति मर्या. ढाढूटोला, पं. क्र.-04
अध्यक्ष : श्रीमती उमादेवी साहू, उपाध्यक्ष : छन्नू साहू
समस्त सदस्य : मो. सफी खान, ताराचंद झोड़े, मदन कामले, भागवतराम साहू, छगन लाडेश्वर,
दरोगा नेताम, देवनारायण नेताम, मिलन परतेती, श्रीमती गैंदीबाई कोवाची
अनिल निषाद
समिति प्रबंधक

पंथी नर्तक डॉ. बारले को मिला पद्मश्री सम्मान

विश्व का सबसे तेज लोक नृत्य पंथी नृत्य जीवन का ऐसा महाकाव्य है, जिसमें अलंकारों की मधुर झंकार ही नहीं वरन रागात्मक अतीत के साथ वर्तमान के संघर्षों का इंद्रधनुषी चित्र भी है. लोक कला के राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले छत्तीसगढ़ में ऐसी गौरवशाली लोक विधा को समृद्ध करने के लिए हजारों लोक कलाकारों को पंथी सम्राट देवदास बंजारे के बाद अब पद्मश्री डॉ.आरएस बारले के रूप में एक और पंथी नृत्य सिरमौर मिल गया है. चालीस वर्षों से देश में बाबा गुरु घासीदास के सतनाम के संदेश के साथ लोक ध्वजा फहरा रहे इस कला रत्न को पद्म अलंकरण से नवाजे जाने से सिर्फ उनका ही हौसला नहीं बढ़ा है बल्कि प्रदेश के सभी लोककलाकारों की हौसला अफजाई हुई है. डॉ. बारले के नए कला अवतार से अब पंथी नृत्य की परंपरा के अधिक समृद्ध होने के साथ कलाकारों के भी अच्छे दिन आने की आशा की जा रही है. डॉ. बारले चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य सहित सभी लोक कलाओं के विकास और लाखों उपेक्षित लोक कलाकारों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के लिए उत्साहवर्द्धक वातावरण विकसित हो. विशेषकर विलुप्त होती लोक कलाओं को बचाने की आवश्यकता है. इसके लिए सरकार को राजधानी में भारत भवन की तरह कला भवन के साथ सभी जिलों में सर्वसुविधायुक्त आडिटोरियम स्थापित कर प्रतिभा दिखाने और लोक कलाकारों के जीविकोपार्जन के लिए मुक्तहस्त से अनुदान व पर्याप्त पेंशन बढ़ाना चाहिए. वे इस दिशा में सभी कलाकारों के साथ अपने प्रयास तेज करेंगे. उनका कहना है कि पद्मश्री सम्मान छत्तीसगढ़ की माटी का सम्मान है. इससे निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा, वे इसे इस लोकांचल के कलाकारों और कद्रदानों को समर्पित करते हैं.

अपनी चार दशकों की कला साधना से देश में पंथी नृत्य के क्षेत्र में एक अलग मकाम बनाने वाले पंथी नृत्य कलाकार भिलाई के डॉ. राधेश्याम बारले की अपने गांव खोला पाटन से दिल्ली तक की दीर्घ कला यात्रा अपूर्व इच्छाशक्ति और अथक संघर्ष की मिसाल है. देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की चमक के पीछे पथरीले रास्ते पर पग-पग चलने का मीलों का संघर्ष छिपा हुआ है. वर्षों लोकोत्सवों में प्रदर्शन व सैकड़ों कलाकारों को मंच देकर अपनी कला से उन्होंने सतनाम की शिक्षा को जन जन तक तो पहुंचाया ही, सरकार के जनकल्याण अभियानों में भी सक्रिय योगदान दिया. इस दौरान मुफलिसी के साथ आयोजनों के संसाधनों को लेकर लेकर कई तरह की परेशानियों से जूझते रहे, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. एक चिकित्सक के रूप में जीवन में आस्था व इसके लिए संघर्ष का भी अनुभव कलायात्रा

का मार्गप्रशस्त करता रहा. छग पंथी नृत्य अकादमी व सतनाम संघम बोरिया टीम के अध्यक्ष 55 वर्षीय पंथी नर्तक डॉ. बारले को पंथी नृत्य की प्रेरणा अपने कलाकार पिता स्व. समारूराम बारले से अपने ग्राम खोला में मिली. पिता की खड़े साज के नाचा और रामसत्ता की गांव में टीम थी, जो रामधुनी, पंथी व नाचा आदि कार्यक्रम किया करती थी. इसमें उनके चाचा शिवदयाल बारले सहित, लेड़गूराम बारले, हरप्रसाद डाहरे व सुखराम कोसरे आदि कलाकार भी थे, जिनके साथ नन्हें राधेश्याम बारले भी थिरकने लगे. इसके बाद प्रसिद्ध पंथी नर्तक देवदास बंजारे से पंथी नृत्य सीखा. मात्र 11 साल की उम्र में 1978 में उन्होंने ग्राम बोदल में पंथी के पथ की शुरुआत की, फिर सदा आगे ही बढ़ते रहे. इस दौरान एमबीबीएस की तालीम व खैरागढ़ संगीत विवि से लोक संगीत में डिप्लोमा फिर बतौर चिकित्सक प्रेक्टिस और पारिवारिक झंझावतों के बीच भी पंथी की लोकयात्रा अनवरत चलती रही. डॉ. बारले बताते हैं कि गुरु तो पिता व स्व. देवदास बंजारे हैं, लेकिन अपनी कला को वे अभ्यास से निरंतर मांझते रहे. प्रदेश व देशभर में पंथीनृत्य से लोकचेतना जगाने के साथ सैकड़ों कलाकारों से जुड़े और हजारों कलाकारों को जोड़ा भी. बीएसपी के छग लोककला महोत्सव और राज्योत्सव से लेकर भोरमदेव उत्सव व खजुराहो उत्सव तक कई लोकोत्सवों में अपनी कला से मंत्रमुगध करने वाले आकाशवाणी रायपुर के बी हाई ग्रेड और दूरदर्शन के नियमित कलाकार डॉ. बारले नई पीढ़ी में पंथी नृत्य के संस्कार डालने में पीछे नहीं रहे. उनके लिए 2016 में विश्व

सांस्कृतिक महोत्सव दिल्ली में 12 सौ पंथी कलाकारों का नृत्य निर्देशन करना यादगार अनुभव है. इसका प्रसारण 172 देशों में हुआ था वहीं वॉयस ऑफ अमेरिका से 13 देशों के प्रसारण में भी उनके नृत्य कौशल को सराहा गया. प्रदेश के दूरदराज गांवों में पंथी कलाकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने उन्होंने 2006 में छग पंथी नृत्य अकादमी का गठन कर 2172 पंथी नृत्य मंडलियों और 65 हजार पंथी कलाकारों को एकजुट किया वहीं वर्षो से सतनाम भजन, खंजेरी, चिकारा, खड़े साज, बांस गीत और डंडा नृत्य आदि विलुप्तप्राय विधाओं को बचाने नृत्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए. साथ ही नक्सलवाद, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर्यावरण जागरूकता जैसे सरकार के कई लोक कल्याण अभियानों में में भी सक्रिय भागीदारी से ग्रामीणों को जागरुक किया. इसके लिए डॉ. बारले को 2012 में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा राज्य अलंकरण गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह -डॉ. भवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा पुरस्कार तथा प्रथम देवदास बंजारे सम्मान जैसे कई अलंकरणों से सम्मानित किया गया.

पंथी महाकुंभ से मिली पहचान नक्सलियों को भी दिया संदेश

अपने मोहक और संदेशपरक पंथी नृत्य से लोककला जगत में अलग स्थान बनाने वाले पंथी नर्तक डॉ. राधेश्याम बारले को उस समय नई पहचान मिली जब उन्होंने प्रदेश व देश में कई प्रदर्शनों और छग पंथी अकादमी से हजारों पंथी कलाकारों को एकजुट करने के बाद भिलाई में 2008 में पंथी महाकुंभ और फिर 2016 में जनजातीय कर्मा महोत्सव का आयोजन किया. इसमें अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले राज्यभर के 14 हजार पंथी व 16 हजार कर्मा नृत्य कलाकारों और हजारों कलाप्रेमियों ने प्रदेश व देश में इस आयोजन की सराहना की. वहीं बस्तर, ओडिशा, झारखंड के नक्सली क्षेत्रों में भी अपनी कला से नक्सलियों को मुख्य मार्ग में आने प्रेरित किया. छग के साथ मप्र, यूपी, बिहार, आंध्र, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड व दिल्ली सहित देशभर में पंथी नृत्य प्रस्तुति के साथ भोजपुर उत्सव, विदिशा महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, भोरमदेव उत्सव आदि कई

पद्मश्री डॉ. बारले का सीएम भूपेश ने किया अभिनंदन

पंथी कलाकार डॉ. बारले को पद्मश्री सम्मान मिलने पर उनका दिल्ली से भिलाई तक भावभीना स्वागत किया गया गया. दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया. समारोह में उप राष्ट्रपति आर वैंकैया नायडू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे. इस अवसर पर मोदी ने डॉ. बारले को शुभकामनाएं देते हुए पंथी व उनकी कलायात्रा के साथ पूछा कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष यानी भाजपा की कैसी स्थिति है. डॉ. बारले का दिल्ली में सतनामी व जाट समाज के लोगों के साथ रायपुर पहुंचने पर भी माना एयरपोर्ट पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया. करीब तीन हजार कलाकारों व कलाप्रेमियों ने स्वागत जुलूस के साथ उनकी अगवानी की. इसके बाद भिलाई पहुंचने पर छग पंथी अकादमी व सतनामी समाज द्वारा दशहरा मैदान रिसाली में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रदेश के सभी जिलों से पहुंचे 16 सौ पंथी कलाकारों ने पंथी नृत्य और सीएम भूपेश बघेल व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उनका अभिनंदन किया. श्री बघेल ने डॉ. बारले के संघर्ष को प्रेरक बताते हुए उन्हें मिले पद्मश्री सम्मान को छत्तीसगढ़ की माटी का सम्मान बताया. डॉ. बारले ने अपने सम्मान को समूचे पंथी कलाकारों का सम्मान बताते हुए लोककला के गुणात्मक विकास की कामना की. इस अवसर पर लोक कलाकारों व सतनामी समाज के लोगों और जन प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में अंचल के कलाप्रेमी उपस्थित थे. सतनामी समाज और जिला कांग्रेस अध्यक्ष (ग्रामीण) निर्मल कोसरे ने समारोह का संचालन और पंथी कलाकार अमृता बारले ने आभार प्रदर्शन किया.

महोत्सवों में भी अपनी कला से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया. इतना ही नहीं उन्होंने महिला सशक्तिकरण, कैंसर व एड्स, साक्षरता, पोलियो व राष्ट्रीय सद्भाव जैसे लोक जागरण अभियानों में 12 सौ मंचीय प्रस्तुति से जाकरूक करने के साथ राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया. इसी तरह जाट कालेज रोहतक,सिद्धि कालेज मप्र व नाट्य कालेज सतना सहित देश के कई महाविद्यालयीन बच्चों को पंथी के साथ अमेरिका व मेक्सिको के पर्यटकों को भी पंथी नृत्य का प्रशिक्षण दिया. उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मानों के साथ सामाजिक समरसता सम्मान, पंथी रत्न सम्मान, सतनाम फेलोशिप अवार्ड, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, कलासाधक सम्मान व दाऊ महासिंह सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया.

प्रदेश में फले-फूले कलाएं व कलाकार

प्रसिद्ध पंथी कलाकार डॉ. बारले पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित होने के बाद खासे प्रसन्न हैं. वे बताते हैं कि इस सबसे बड़े प्रतिष्ठित सम्मान से उनका हौसला बढ़ेगा और अब दोगुने उत्साह से पंथी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे. इस सम्मान का श्रेय वे सभी पंथी कलाकारों व कलाप्रेमियों के साथ अपने गुरु पिता स्व. समारूराम बारले, माता गैंदीबाई तथा बहन लोककलाकार अमृता व गीता बारले को देते हैं. वे चाहते हैं कि पंथी को राज्य व देश के साथ अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले. इसके लिए 50 हजार पंथी कलाकारों के साथ पंथी नृत्य का प्रदर्शन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित करें. साथ ही छग में सभी लोककलाओं व लोककलाकारों के समुचित विकास के लिए भोपाल के भारत भवन की तरह रायपुर में लोककला भवन बने और हर जिले में सुविधायुक्त आडिटोरियम का निर्माण सरकार करे. इससे विलुप्त होती लोककलाओं को पुर्नजीवित करने साथ उदीयमान कलाकारों को मंच भी मिलेगा. प्रदेश में 5 लाख लोककलाकार हैं. साथ ही कलाकारों की प्रतिभा व जीविकोपार्जन के लिए अनुदान, पेंशन में बढ़ोत्तरी की जाए. कुछ ही कलाकारों को मात्र 2 हजार पेंशन मिल रही है,इसे 5 हजार करने से बुजुर्गों को मदद मिलेगी. कोरोनाकाल में कई कलाकार चल बसे व अनेक गरीब कलाकार कोई मदद नहीं मिलने से दाने दाने को तरस गए. सैकड़ों कलाकार मंच के साथ गरीबी के चलते बीमारी व दीगर परेशानियों से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोककला के मौलिक विकास के लिए लोक कलाओं को आधुनिकता से बचाने के साथ लोक कला व छत्तीसगढ़ी फिल्मी कलाकारों को अलग-अलग रखा जाए. सरकार लोककला प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर नए कलाकारों की प्रतिभा का विकास करे और अंतराष्ट्रीय महोत्सवों को भी बढ़ावा दे. इसी तरह राज्योत्सव पर लोकनृत्य के लिए दिया जाने वाला दाऊ दुलार सिंह साव मदराजी सम्मान हर साल लोक नृत्य को ही मिलने से इस विधा के लोगों को प्रेरणा मिलेगी. यह पुरस्कार पिछले पांच साल से लोकसंगीत के कलाकारों को दिया जा रहा है. छग पंथी नृत्य अकादमी को शासन से मान्यता मिलने से पंथी का विकास होगा. लोक कला संस्थान में भी प्रमुख के रूप में कला के विशेषज्ञ कलाकारों की ही नियुक्ति हो,ताकि कलाकारों की प्रतिभा के साथ न्याय हो सके. डॉ. बारले बताते हैं कि उनके दो बेटे भोजराज व तुशांत की भी पंथी में रुचि है, वे अभी पढ़ रहे हैं. बेटी नर्स है और पत्नी महेश्वरी गृहिणी है लेकिन लोककला की अच्छी समझ रखती हैं.

चायकुर (नेतानार) में निवासरत

आदिवासियों के आदर्श गुंडाधुर के पड़पोते ने परिवार सहित किया मतांतरण

फैसले से धुरवा समाज स्तब्ध

हेमंत कश्यप

बस्तर का विशाल आदिवासी समाज जो क्रांतिवीर शहीद गुंडाधुर को अपना आदर्श मानते हैं और जल- जंगल- जमीन के लिए लड़ना सिखाने वाला मानते हुए उनकी याद में प्रतिवर्ष भूमकाल दिवस मनाता है. उसी क्रांतिवीर के पड़पोते ने सपरिवार धर्म परिवर्तन कर लिया है. इस बात से धुरवा समाज स्तब्ध है और अब इन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटाने की कोशिश कर रहा है.

कौन हैं गुंडाधुर

क्रांतिवीर शहीद गुंडाधुर मूलतः गोपापदर (नेतानार) निवासी थे. उन्हें बस्तर के ऐतिहासिक भूमकाल आंदोलन का जनक माना जाता है. उन्होंने जल- जंगल- जमीन आदिवासियों का है, का नारा बुलंद करते हुए समस्त आदिवासी समाज को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया था. लाख जतन के बावजूद अंग्रेज हुकूमत गुंडाधुर को पकड़ नहीं पाई लेकिन उसके अभिन्न मित्र ढेबरीधुर को जगदलपुर बाजार मध्य इमली पेड़ में सरेआम फांसी पर लटका दिया था. तब से बस्तर का आदिवासी समाज गुंडाधुर को अपना आदर्श मानते हुए प्रतिवर्ष दस फरवरी को भूमकाल दिवस मना उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है.

नेतानार में हैं गुंडाधुर के वंशज

जिला मुख्यालय से लगभग 35 किमी दूर नेतानार के चायकुर और गोपापदर बस्ती में गुंडाधुर के वंशज निवासरत हैं. गुंडाधुर के वंशज ही स्थानीय नेतानारीन देवी के परंपरागत पुजारी भी हैं .शहीद गुंडाधुर का परपोता जयदेव और परदेसी नाग चायकुर में खेती- किसानी करते हैं. परदेसी नाग सहित माता मांडी, बहन वैजयंती, पत्नी मनीता ने धर्म परिवर्तन कर लिया है.

पहले मां ने किया मतांतरण

परदेसी नाग ने बताया कि परिवार में सबसे पहले उसकी मां मांडी गेह्रूंपदर चर्च जाकर धर्म परिवर्तन की थीं. तीन साल पहले दरवाजा बनाते समय परदेशी को चोट लगी थी. झाड़-फूंक से वह ठीक नहीं हुआ तो वह भी गेह्रूंपदर चर्च जाकर अपनी बहन वैजयंती और पत्नी मनीता के साथ स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया. अब वह क्रिसमस और ईस्टर भी मनाने लगा है. शहीद गुंडाधुर के वंशजों द्वारा मतांतरण किए जाने की जानकारी बजरंग दल और विश्व प्रसिद्ध विश्व हिंदू परिषद को भी है किंतु वह भी नेतानार क्षेत्र में हो रहे मतांतरण को रोकने की दिशा में अब तक कोई विशेष पहल नहीं कर पाई है.

गुंडाधुर स्मारक से भी छेड़छाड़

बस्तर जिले का नेतानार ग्राम बस्तर के चर्चित भूमकाल आंदोलन के जनक क्रांतिवीर शहीद गुंडाधुर की जन्मस्थली है. इस गांव को विशेष पहचान देने के लिए लाखों रुपए खर्च कर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहां शहीद गुंडाधुर की विशाल प्रतिमा स्थापित कर पार्क विकसित किया गया है. इसके साथ ही नेतानार को गौरव ग्राम घोषित किया गया है. नेतानार चौक में जहां पर क्रांतिवीर गुंडाधुर की प्रतिमा स्थापित की गई है. उसके ठीक सामने गुंडाधुर की जीवनी तथा उनके उल्लेखनीय कार्यों से संदर्भित दो शिलालेख स्थापित किए गए थे. शरारती तत्वों ने इसे भी शिलालेखों से हटा दिया है, परंतु गुंडाधुर को अपना आदर्श मानने वालों ने भी इस संदर्भ में कोई रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज नहीं कराई है. इसलिए इस क्षेत्र के कुछ चर्चित लोगों पर शक की सुइयां घूम रही हैं.

समाज में लौटाने प्रयास जारी

शहीद गुंडाधुर के वंशज चायकुर-गोपापदर बस्ती (नेतानार) में निवासरत हैं. चायकुर में निवासरत गुंडाधुर वंश के चार सदस्यों द्वारा धर्म परिवर्तन करने की जानकारी धुरवा समाज को मिली है. परदेसी के बड़े भाई जयदेव तथा अन्य सदस्यों को परदेसी तथा उसके परिजनों को परिवर्तित धर्म छोड़ने हेतु समझाने कहा गया है, अगर वह बात नहीं मानता है तो दिसंबर महीने में समाज की बैठक चायकुर में आहूत की जाएगी.

गंगाराम कश्यप, संभागीय महासचिव धुरवा समाज, बस्तर

बढ़ती महंगाई के बीच छत्तीस

लगातार बढ़ती महंगाई के बीच छत्तीसगढ़ में बिजली सुलभ और सस्ती रखने के लिए शासन कई स्तरों पर प्रयास कर रहा है. राज्य में शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है. विभिन्न योजनाओं द्वारा कृषकों, घरेलू उपभोक्ताओं, इस्पात उद्योगों को राहत दी जा रही है. बिजली आपूर्ति को सुचारू करने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने ढाई साल में 33/11 केवी क्षमता के 102 नए विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण किया है. छत्तीसगढ़ देश का पहला “पावरकट फ्री” प्रदेश है.

ऊर्जा किसी भी राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है. आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में विद्युत की सतत् उपलब्धता एवं निर्बाध वितरण प्रणाली का होना महत्वपूर्ण है. छत्तीसगढ़ में विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पांच कंपनियों की स्थापना की गई है. सीएसपीएचसीएल (होल्डिंग कंपनी), सीएसपीजीसीएल (पावर जनरेशन), सीएसपीटीसीएल (पावर ट्रांसमिशन), सीएसपीडीसीएल (पावर डिस्ट्रिब्यूशन) तथा सीएसपीटीसीएल (पावर ट्रेडिंग) कंपनी के माध्यम से उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण एवं ट्रेडिंग को अंजाम दिया जा रहा है.

मोर बिजली ऐप

विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए “CSPDCL MOR BIJLEE” ऐप लांच किया गया है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. राज्य के 59.03 लाख उपभोक्ता इसका लाभ ले रहे हैं. ऐप के माध्यम से नया कनेक्शन, विद्युतभार घटाने-बढ़ाने, घरेलू बिल की गणना, टैरिफ की जानकारी, दो वर्षों का भुगतान रिकार्ड, मीटर रीडिंग, लाइन टूटने, ट्रांसफार्मर में खराबी आदि की सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है. ऐप के जरिए गड़बड़ी की फोटो खींचकर संबंधित अधिकारियों को भेजा सकता है.

केन्द्रीकृत कॉल सेन्टर

राजधानी रायपुर में 30 लाइन का कॉल सेन्टर 1912 स्थापित किया गया है जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सूचना टेलीफोन, मोबाइल, ई-मेल अथवा ऑनलाइन दी जा सकती है. निराकरण की सूचना उपभोक्ता को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा दी जाती है. www.scpdcl.co.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

आसान भुगतान प्रणाली

वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ता अपने विद्युत देयकों का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग (44 अधिकृत बैंक) द्वारा कर सकते हैं. इसके अलावा 133 एटीपी मशीनों द्वारा भी बिजली बिलों का भुगतान किया जा सकता है.

किसानों को 7500 यूनिट तक बिजली फ्री

किसानों को 3 हार्स पावर (अश्वशक्ति) वाले पम्पों पर 6000 यूनिट प्रतिवर्ष एवं 3-5 हार्स पावर वाले पम्पों पर 7500 यूनिट प्रतिवर्ष बिजली मुफ्त दी जाती है. इससे ऊपर की खपत पर फ्लैट रेट पर बिजली खरीदने का विकल्प दिया जाता है. अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए बिजली खपत की कोई सीमा नहीं है. उनके द्वारा कृषि कार्यों में उपयोग की गई बिजली पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है.

विद्युत अधोसंरचना विकास योजना

जीरो पावर कट का लाभ उपभोक्ताओं को तभी मिल सकता है जब पारेषण एवं वितरण की सुचारू व्यवस्था हो. इसके लिए अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की गई है. नए 33/11 केवी के ट्रांसफार्मरों की स्थापना के साथ साथ 33 एवं 11 केवी लाइनों का निर्माण किया जा रहा है. इस तरह बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए 1281

गढ़ में सस्ती-सुलभ बिजली

उपभोक्ताओं को राहत

बढ़ती महंगाई के बीच उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं. घरेलू उपभोक्ताओं से 400 यूनिट तक खपत पर 4.50 रुपए के बजाए 2.30 रुपए प्रति यूनिट लिया जाता है. योजना के अंतर्गत नवंबर 2021 तक 40 लाख उपभोक्ताओं को 2060 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है.

इस्पात उद्योगों को मंदी से उबारने ऊर्जा प्रभार पर 0.80 प्रति यूनिट की रियायत दी जा रही है. मार्च 2020 तक 413 उपभोक्ताओं को 418 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है.

18 लाख बीपीएल परिवारों को प्रति माह 30 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाती है. इसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है.

करोड़ रुपये के कार्य किये जा चुके हैं और 211 करोड़ के कार्य प्रगति पर है. मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत 2021-22 के बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. योजना के अंतर्गत 33/11 केवी के 24 नए उपकेन्द्रों की स्थापना की जा रही है.

मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना

योजना के तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था सुचारू की जा रही है. 2 वर्ष में 1288 कार्यों को संपादित किया जा चुका है जिसपर 59 करोड़ रुपए का खर्च आया है.

मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना

जिन गांवों में आंशिक विद्युतीकरण हुआ है वहां मजरा-टोला/बसाहटों तक विद्युतीकरण किया जा रहा है. ये बसाहटें राज्य में संचालित राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल नहीं हैं. ढाई वर्ष में 3390 कार्य संपादित किये जा चुके हैं जिन पर 168 करोड़ रुपए का खर्च आया है.

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बस्तर क्षेत्र मे 220 केवी के दो उपकेन्द्रों की स्थापना जगदलपुर एवं नारायणपुर में की गई. बीजापुर में 132 केवी का एक उपकेन्द्र तथा जगदलपुर के 400 केवी उपकेन्द्र से बारसुर तक 89 किलोमीटर लंबी 220 केवी पारेषण लाइन का निर्माण किया गया है.

रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र उरला, बिरगांव में मौजूदा 132 केवी लाइनों के पुराने पैंथर कंडक्टर को नई तकनीक से बनी उच्च क्षमता वाले एचटीएलएस कंडक्टर से बदल दिया गया है. इससे क्षेत्र की पारेषण क्षमता 50 मेगावाट बढ़ गई है.

योजनाओं की फंडिंग

कुछ बड़े कार्य फंड नहीं होने के कारण रुके हुए थे. बीते ढाई वर्षों में 516 करोड़ रुपए इन कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया जिससे कार्य पूरा हो गया. इनमें निम्न उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण शामिल है –

1. 400 केवी उपकेन्द्र कुरुद (धमतरी)
2. 200 केवी के उपकेन्द्र जगदलपुर, नारायणपुर एवं बिलासपुर (धरदेही)
3. 132 केवी के उपकेन्द्र बीजापुर तथा उदयपुर

निर्माणाधीन परियोजनाएं

1. 220 केवी उपकेन्द्र पाटन
2. 132 केवी उपकेन्द्र खरमोरा, सिलतरा फेस-2, इंदामारा, इंदागांव, खैरागढ़ एवं मठखरोरा

3. 132 केवी उपकेन्द्र छावनी एवं अमलेश्वर के लिए कार्यादेश जारी
4. 132 केवी उपकेन्द्र बैजलपुर के लिए निविदा जारी
5. 220 केवी उपकेन्द्र सेमरिया, दलदलसिवनी तथा अहिवारा की प्रशासनिक स्वीकृति
6. 132 केवी उपकेन्द्र मस्तुरी, बलौदा, बेतर, टेमरी, गुल्लू (आरंग) की प्रशासनिक स्वीकृति
7. 400 केवी उपकेन्द्र बिलासपुर के लिए प्रशासनिक स्वीकृति
8. 400 केवी उपकेन्द्र अम्बिकापुर, 220 केवी उपकेन्द्र राजिम, कांकेर, धरमजयगढ़, गुमा/बारा/कारा तथा 132 केवी उपकेन्द्र सरोरा, केशकाल, मेटल पार्क, हांफा (उस्लापुर) के लिए भूमि चयन/आवंटन की प्रक्रिया जारी है.

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्धियां

- 2018-19 में छत्तीसगढ़ ने 21552.399 मिलियन यूनिट विद्युत का रिकार्ड उत्पादन किया. इसमें तापीय विद्युत 21277.503 मिलियन यूनिट, जलीय विद्युत 268.809 मिलियन यूनिट, पीएलएफ विद्युत 74.05 तथा अन्य सह-उत्पादन 6.087 मिलियन यूनिट शामिल है. इस अवधि में सहायक विद्युत खपत (7.40%) भी न्यूनतम रहा. 2017-18 में यह खपत 7.64% थी.
- लक्ष्य से अधिक उत्पादन – 2018-19 में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 20842 मिलियन यूनिट एवं राज्य नियामक आयोग द्वारा 21157.96 मिलियन यूनिट का लक्ष्य दिया गया था. लक्ष्य से अधिक कुल 21552.399 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया.
- लांग डिस्टेंस कोल कन्वेयर से बढ़ा उत्पादन : 2019-20 में हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में लांग डिस्टेंस कोल कन्वेयर के माध्यम से एसईसीएल के नये कोल बंकर से कोयले की आपूर्ति प्रारंभ हो गई. इस कोल बंकर की क्षमता 20000 मीट्रिक टन है. फलस्वरूप 2020-21 में इस ताप विद्युत गृह ने 92.82% संयंत्र उपयोगिता गुणांक के साथ 4065.531 मिलियन यूनिट का सर्वकालिक रिकार्ड उत्पादन किया.

विवरण	2018	2021
400 केवी उपकेन्द्र	3	4
220 केवी उपकेन्द्र	23	25
132 केवी उपकेन्द्र	92	94
400 केवी लाइनों की लंबाई	1916 किमी	1918 किमी
220 केवी लाइनों की लंबाई	3602 किमी	4032 किमी
132 केवी लाइनों की लंबाई	1664 किमी	7192 किमी
पारेषण हानि (ट्रांसमिशन लॉस)	3.09 प्रतिशत	2.96 प्रतिशत

- **निरंतर संचालन का कीर्तिमान** – 2020-21 में डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व इकाई-1 ने 94.38% प्लांट उपलब्धता घट व 87.77% PLF के साथ 14.03.2020 से 01.09.2020 (171 दिन 5:20 मिनट) तक निरंतर इकाई संचालन का कीर्तिमान प्राप्त किया.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीएसपीजीसीएल के जल विद्युत गृहों ने 462.526 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है. पिछला कीर्तिमान 2001-02 (403.25 मिलियन यूनिट) का था.
- मिनीमाता हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह. माचाडोली द्वारा अगस्त 2020 में 87.74 मिलियन यूनिट विद्युत का सर्वकालिक अधिकतम मासिक उत्पादन किया गया.
- वित्तीय वर्ष 2021 इस विद्युत गृह ने कुल 419.18 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया जो राज्य स्थापना के बाद का सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन है.

राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन में अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करते हुए वर्ष 2020-21 में 70.08 पीएलएफ के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है. इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृहों का औसत पीएलएफ 51.49 प्रतिशत तथा राज्य ताप विद्युत गृहों का औसत पीएलएफ 42.12 रहा. छत्तीसगढ़ ने पिछले तीन वर्षों में इसमें लगातार सुधार करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है.

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 74.05 पीएलएफ के साथ चौथे स्थान पर रहा.
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 67.31 पीएलएफ के साथ तीसरे स्थान पर रहा.
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 70.08 पीएलएफ के साथ प्रथम स्थान पर रहा.

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़
चैतन्य बघेल
आशीष वर्मा
मनीष बंछोर
जनसरोकार की
छत्तीसगढ़ सरकार
के तीन वर्ष पूरा होने पर
वंदन....
अभिनंदन...
मान. श्री भूपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
संस्थापकः स्व. श्री बीरा सिंह
संबंधित प्रतिष्ठान...
• हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी, हथखोज, भिलाई
• दलबीर सिंग एण्ड संस, रिसदा, बलौदाबाजार
• शिवा मिनरल्स, पथरिया, नंदिनी
• एसबीएस हॉस्पिटल, जीई रोड कैम्प-2, भिलाई
इंद्रजीत सिंह (छोटू)

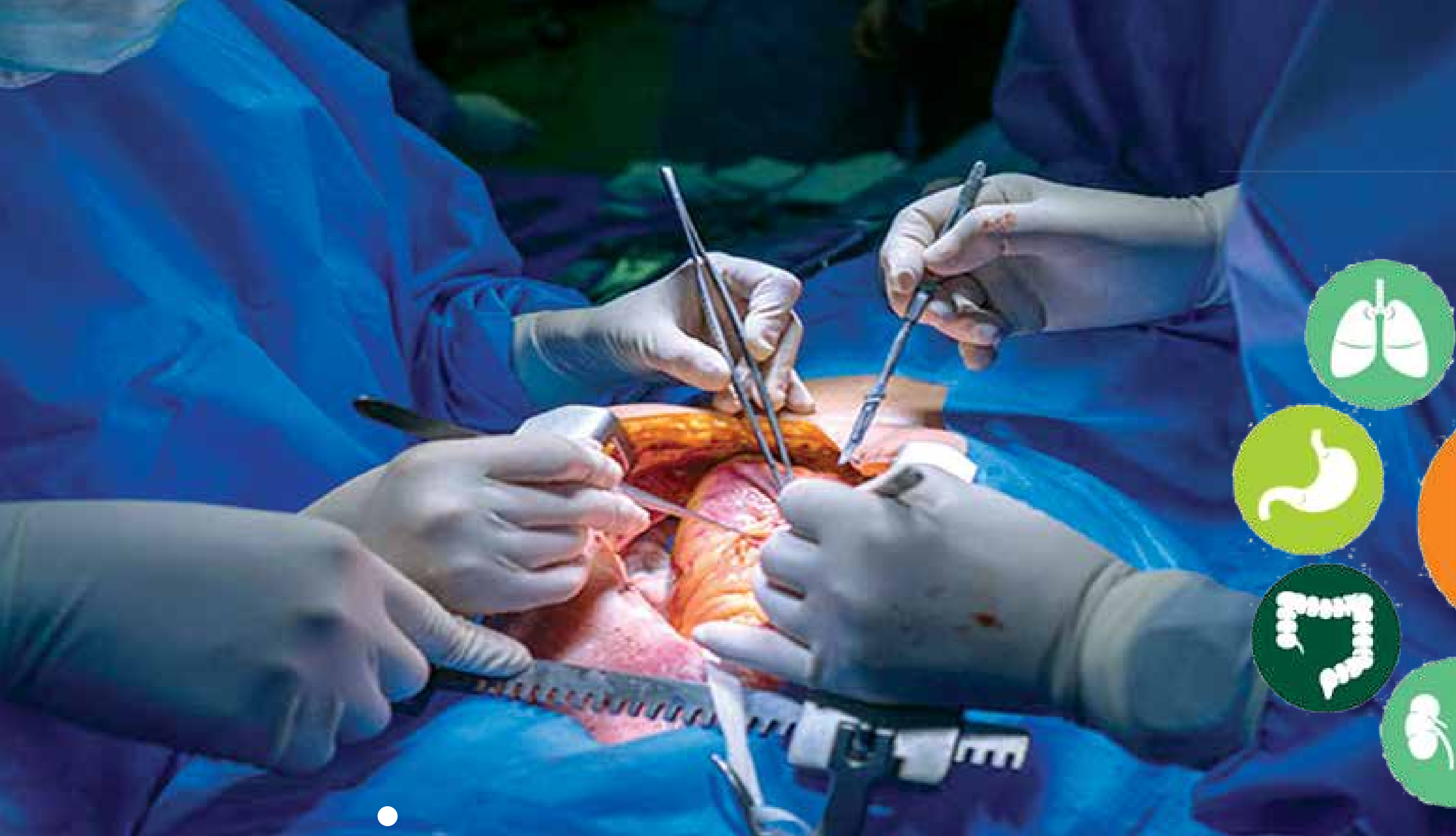

अंगदान महादान

दीपक दास

किसी व्यक्ति के जीवन में अंगदान के महत्व को समझने के साथ ही अंगदान करने के लिए आम इंसान को प्रोत्साहित करने 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने की उपयोगिता अंगों की अनुपलब्धता के कारण बढ़ती जा रही है. वैसे भारत में प्रतिवर्ष 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है. देश में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों की मृत्यु विभिन्न अंगों के फेल हो जाने से हो जाती है. भारत में हर 10 लाख में सिर्फ 8-8 डोनर ही अंगदान करते हैं. समय पर अंग नहीं मिल पाते इसलिए 2 लाख व्यक्ति लीवर की बीमारी और 50 हजार व्यक्तियों की दिल की बीमारी से मौत हो जाती है. लगभग डेढ़ लाख व्यक्ति किडनी ट्रांसप्लांट के इंतजार में रहते हैं, लेकिन सिर्फ 5 हजार व्यक्तियों की ही किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है. यही कारण है कि बीमार व्यक्तियों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत होते हुए भी उनकी मौत हो जाती है और उन्हें ऑर्गन मिलता ही नहीं है. लाखों व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग के खराब हो जाने पर उसकी जगह किसी के दान किए अंग जोहते रहते हैं. शरीर के किसी अंग के काम न करने की वजह से वे निराश हो जाते हैं. वे भी जीना चाहते हैं, लेकिन उनसे जीवन की सांसें गिनती की रह जाती है. उसके संकट में पड़े जीवन में जीने की उम्मीद को बढ़ाने में अंग प्रत्यारोपण एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है.

अंगदान के बारे में डर और प्रतिज्ञा

अंगदान करने से मोक्ष नहीं मिलता. मौत के बाद भी आत्मा घूमती रहती है. हिंदू धर्म में अंगदान नहीं किया जाता. मेरी उम्र कम है. मैं दुबला पतला हूं. कुछ ऐसे ही भ्रम आज भी हमारे समाज में फैले हैं, जो ऑर्गन डोनेशन की राह में रोड़ा हैं. लाखों लोग मौत की शैया पर इंतजार करते रहते हैं कि कौन भगवान बनकर आत्मा और उन्हें गिफ्ट में ऑर्गन डोनेट कर नया जीवन दे जाएगा.

वरिष्ठ नागरिक दिवस की सार्थकता उनकी सुरक्षा में

फियोना मिलेश ने अंगदान के लिए व्यापक वातावरण का निर्माण किया. उन्होंने कहा कि बिना यह देखे कि मेरे अंग किसी और के काम आ सकते हैं, मेरे अवशेषों को जलाने या दफनाने का क्या फायदा. अंगदान की दयालुता ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन

अंगदान करने वालों में तमिलनाडु अग्रणी

भारत में सरकारी स्तर पर उपेक्षा इसकी बड़ी वजह है. जागरूकता भी काफी कम है. यही वजह है कि भारत में बड़ी संख्या में मरीज अंग प्रत्यारोपण के लिए इंतजार करते-करते दम तोड़ देते हैं. भारत में उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति बहुत खराब है, जबकि दक्षिण भारत अंगदान के मामले में जागरूक प्रतीत होता है. खासतौर पर तमिलनाडु जहां प्रति 10 लाख लोगों पर अंगदान करने वालों की संख्या 136 है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुआ कानून

छत्तीसगढ़ कुछ विरले राज्यों में से है, जिसमें फरवरी 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कानून पारित होने के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य का स्वास्थ्य विभाग अभी तक न तो राज्य इकाई गठित कर सका न ही इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तथा नियमावली बना सका।

सकते हैं, अंधे देख सकते हैं. आप जो अंगदान करते हैं वो किसी और को जिंदगी में एक और जीने का मौका देता है. वह आप का कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, एक दोस्त हो सकता है, कोई आपका प्यारा हो सकता है या आप खुद हो सकते हैं. इसलिए हर व्यक्ति को अंगदान का संकल्प लेना चाहिए. अंग प्रतिरोपित व्यक्ति के जीवन में अंगदान का संकल्प लेना चाहिए. अंग प्रतिरोपित व्यक्ति के जीवन में अंगदान करने वाला व्यक्ति एक ईश्वर की भूमिका निभाता है.

क्या आप जानते हैं?

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का अपेक्षित प्रसार हुआ है. प्रदेश के कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सभी प्रकार के अंग प्रत्यारोपण की उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है. बड़ी संख्या में अंगदान हेतु प्रतीक्षारत गरीबों के लिए सीमित माला में ही अंग दानदाताओं का उपलब्ध होना इन मरीजों की बढ़ती संख्या और जल्दी मृत्यु का मुख्य कारण है. पूरे देश में प्राकृतिक रूप में मृत मरीजों (कैडेवर) के अंगदान का महत्व बढ़ा है. देश के सभी अग्रणी राज्यों कैडेवर ऑर्गन डोनेशन एक्ट को केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार अपनाया है. विभिन्न अंगों के दान के कानूनी प्रावधान और गाइडलाइन के लिए भारत सरकार ने 1994 में Transplantion of Human Organs And Tissue Aet (THOTA) पारित किया था. तामिलनाडू देश का पहला राज्य बना जहां इसे कानूनी रूप से अपनाया गया.

भारत में प्रतिवर्ष 27 नवंबर को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन जनता को अंगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रोत्साहन व जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं.

प्रत्यारोपण की राह देख रहे 5 लाख से अधिक मरीज

देश में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक लोगों को मृत्यु विभिन्न अंगों के फेल होने से हो जाता है. यदि इन व्यक्तियों को अपने परिवार या अन्य किसी व्यक्ति से जिससे इसका मैचिंग संभव हो जरूरत का अंग मिल जाए तो वह व्यक्ति सफल ऑपरेशन के पश्चात सामान्य जीवन जी सकता है.

छत्तीसगढ़ में कैडेवर ऑर्गन डोनेशन एक्ट लागू हो जाने से प्रतिवर्ष कई परिवार अपने प्राकृतिक रूप से मृत रिश्तेदार के अंगदान करने के इच्छुक रहते हैं. एक प्राकृतिक रूप से मृत व्यक्ति की दो किडनी, दो फेफड़े, हृदय, पैंक्रियास और लीवर कई मरीजों की जान बचा सकते हैं. गंभीर रूप से बीमार अंगदान हेतु प्रतीक्षारत मरीजों के लिए एक नई किरण और संजीवनी साबित हो सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति अपने अंगदान से 11 लोगों को जीवनदान दे सकता है. पिछले कुछ वर्षों से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि मृत्यु पश्चात अंगदान को प्रोत्साहित किया जा सके और नियम बनाए जा सकें, ताकि मृत्यु के पश्चात वो लोग अपने अंगदान करना चाहते हैं वो अंगदान कर लोगों को जीवनदान दे सकें. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पहल करने की जरूरत है. इसके लिए समाज और मीडिया को भी सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी.

इन चिकित्सकों ने किया अंगदान का आह्वान

डॉ. महेश सिन्हा, प्रेसिडेंट, आईएमए, छत्तीसगढ़
डॉ. राकेश गुप्ता, चेयरमेन, हास्पिटल बोर्ड, आईएमए, छत्तीसगढ़
डॉ. विकास अग्रवाल, प्रेसिडेंट, आईएमए, रायपुर
डॉ. आशा जैन, महासचिव, आईएमए, रायपुर
डॉ. अनिल जैन, चेयरमेन, हास्पिटल बोर्ड, रायपुर

आजादी यूं ही नहीं मिल गई

एक सेनानी की बेटी का संस्मरण

वीणा वर्मा

हमें आजादी मिली भी तो पाकिस्तान बांटकर. 14 अगस्त को वे अपना स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं. इस अधूरी आजादी की भरपाई तब हुई जब स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्तगालियों से डॉ. राम मनोहर लोहिया और अन्य दिग्गजों के नेतृत्व में भारतभर के और गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने गोवा को आजाद कराया. अंग्रेज शासन में जो सैनिक थे सर्वाधिक भारतीय ही थे. स्थानीयता का पुट था. इसलिये ये थोड़ी नरमी भी बरत लेते थे. लेकिन गोवा में राज कर रहे पूर्तगालियों में निष्ठुरता अधिक थी.

पाटन क्षेत्र में एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हुए जो गोवा मुक्ति संग्राम में भी भाग लेने वाले अकेले सेनानी हुए. इन्हीं सेनानी स्व. खूबीराम कश्यप (डंगनिया) की पुत्री वीणा ने पिता द्वारा बताई घटनाओं का संस्मरण बताया है. वे कहते थे-हमारा देश पूरी तरह से आजाद हो इसलिये हमारा एक ही नारा था, गोली डंडा खायेंगे, गोवा हम जायेंगे. गोवा में हम सेनानी एक जगह एकत्रित हुए इनमें भारत के अन्य स्थानों की तरह छत्तीसगढ़ के दुर्ग रायपुर और अन्य क्षेत्रों से भी थें. गोवा छोडों, वन्दे मातरम् का नारा हम लगाते रहते थे. हमें गिरफतार कर लिया गया. हमें भूखा प्यासा रखा गया. भारी बारीश होने लगी में तो हम डटे थे ही. फिर भी डटे रहे. रात होने लगी. हम भींग कर कॉपने लगे. हमने सुरक्षित जगह की मॉग की तो बामुश्किल एक कमरा दिया. इस कमरे में भी हम लगभग ठुसने की स्थिति में थें. और बाहर से कमरा बंद कर दिया गया था. गर्मी से सॉस लेना दुभर हो गया. फिर एक तरकीब हमने लगाई, कमरा खपरैल वाला (कवेलू) था. हम एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर कुछ खपरैल हटाई तब कहीं सॉस में सॉस आई, किसी तरह रात बीती भूखे प्यासे यहाँ से हमें लेजाकर जेल में रखा गया. ले जाते हुए भी सैनिक हमें मारते पीटते रहे. दिन गुजरता रहा. यहाँ हमसे सब काम कराये जाते. पिता (खूबीराम जी) जिस काम को नहीं करना चाहते थे मना कर देते थे तब कोड़ों से मारा जाता. फिर भी जिद छोड़ी नहीं. नारे लगाते रहे. फलतः उन्हें रिंग तो लगा हुआ था ही, चैन से बांध दिया गया. बेली से बॉधा गया. चलने में परेशानी होने लगी, लघुशंका जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती. बाहर सिपाही जगह जगह पहरे पर खड़े थे. जेल में शंका के आधार पर धक्का देकर आगे फेकते जाते. इस तरह हम वहाँ से निकल पाते. जेल समुद्र ही था, किनारे ही था. धक्के के कारण कभी-कभी समुद्र में गिरते बचे. साथियों को सहारा देकर बचाया. पिता को बागवानी या कुछ अप्रिय काम दिया गया तो काम करने के बजाय उखाड़ कर फेंक देते विरोध किया बात नहीं मानते . वे कहते- हम गुलामी करने के लिए नहीं आजादी लेने आये हैं के पास ऐसा कहने करने पर इनकार को देखते परिणाम में कोड़े पड़ते रहे. वे कहते-कोड़े पड़ते और मैं देश की पूर्ण आजादी के लिए खुश होता रहा. एक दिन हमें मारते हुए समुद्र में फेंका गया. हम साथी एक दूसरे को सम्हालते हुए वापस हुए. अधिकारियों ने हमारी बातें कुछ सुनी| इन घटनाओं के चलते कुछ समय बाद ही गोवा आजाद हुआ.

मेरे पिता स्नान के बाद तेल मलकर धुप में खड़े हो जाते थे. तब मैं उनके शरीर पर गोवा वाले निशान के बारे में पूछ लेती थी. उम्र समझने की हो गई थी. वे कहते, पगली ये चोट के निशान नहीं देश के नाम से प्रसाद मिला है. आजादी और इसके लिए पड़े कोड़े के निशान अब भी मेरे जेहन (चित) में है. उस प्रसाद रूपी निशान का स्मरण कर मै अब भी सिहर उठती हूँ. अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भी वे वर्षो जेल में रहे तब उन्हें काल कोठरी की भी सजा दी गई थी.

उनका संस्कारिक प्रभाव मेरे सगे और अन्य परिजनों और परिचितों पर पड़ा है. उन्होंने गलत के लिए भी लडना सिखाया. कहीं जाकर मौन रहने से समस्या का समाधान नहीं होता. अत्याचारियों और अन्यायियों से जुझना भी पड़ता है. सच्चे मन से श्रमदान से भी मदद किया जा सकता है. पड़ोसियों से पारिवारिक व्यक्ति की तरह व्यवहार करें. हम छोटे भाई बहन (माघव, तेजस्वी, बसंत, हेमत, और मुझसे छोटी ममता) और कोई आसपास के कभी झगड़ पड़ते तो कहते खाने दे ना खाये. इसका मतलब - वे बताते एक गाय घास खा रही थी उसे देखकर कुत्ता लगातार भौंक रहा था. गाय कहती है खाने दे न खाये दुष्ट, यह कहकर गाय वहां से चली गई. कुत्ता घास नहीं खाता तो भी भौंक रहा होता है. पिता कहते, अपना काम खुद करों. किसी पर दोषा रोपण से दूर रह मदद करने से काम में आसानी होती है. सलाह लेने की चीज है. सहयोग सम्मान से जीवन आसान होता है. वीणा बताती हैं पिता जब गोवा गये तो पिता ने हमारी मॉ इन्दुमती को नहीं बताया था. वे गर्भ (बसंत) में थी. वे तब जान पाई जब रेलवे स्टेशन से गोवा से लौटे सेनानियों के सम्मान में ऐतिहासिक उपस्थिति वाली जुलूस में दुर्ग की सड़कों पर स्वागत के लिए भ्रमण कराया गया. पिता का नारा था राजनीति दुकानदारी नहीं सेवा है. आपात काल के दौरान लोक सभा चुनाव में सांसद की टिकिट दी जा रही थी. विधायकी के लिए भी प्रस्ताव था लेकिन पद की राजनीति नहीं करने चुनाव नहीं लड़ा.

पदभार ग्रहण समारोह
में पधारे अतिथियों का
आभार
श्री निर्मल कोसरे जी
महापौर
नगर पालिक निगम, भिलाई चरौदा
श्री कृष्णा चन्द्राकर जी
सभापति
नगर पालिक निगम, भिलाई चरौदा
पार्षदगण
श्रीमती ठामेश्वरी साहू वार्ड-1
श्रीमती संतोषी निषाद वार्ड-3
भुपेन्द्र वर्मा वार्ड-4
मनोज डहरिया वार्ड-5
श्रीमती दिप्ती वर्मा वार्ड-6
संतोष तिवारी वार्ड-7
हेमंत वर्मा वार्ड-8
श्रीमती शारदा मदनकर वार्ड-13
श्रीमती देव कुमारी भल्लावी वार्ड-14
डे साहब वर्मा वार्ड-15
अभिषेक वर्मा वार्ड-18
मनीष वर्मा वार्ड-19
टेनेन्द्र ठाकरे वार्ड-23
एस. वेंकट रमना वार्ड-25
मोहन साहू वार्ड-26
एम. जॉनी वार्ड-27
ईश्वर साहू वार्ड-30
श्रीमती भारती सुर्यवंशी वार्ड-31
रविन्द्र हरपाल वार्ड-33
ललित दुर्गा वार्ड-35
श्रीमती सुष्मा चंद्राकर वार्ड-36
कामता साहू वार्ड-39
विनीत - समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, भिलाई -चरौदा
कृपया कोविड प्रोटोकाल का पालन करें। (दो गज दूरी मास्क है जरूरी)

मान. श्री केशव बंछोर को
रिसाली नगर निगम के
सभापति बनाए जाने पर
हार्दिक
बधाई
: विनीत :
समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
श्री केशव बंछोर जी
सभापति, नगर पालिक निगम रिसाली

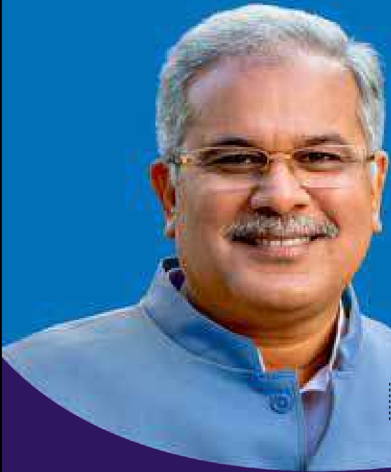

न्याय, सरोकार व इच्छाशक्ति से बना
छत्तीसगढ़ मॉडल

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

किसान
- कर्ज मुक्त किसान, अनुदान राशि से बढ़ी आय और पैदावार
- भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता

पशुपालक
- सरकार द्वारा गोबर खरीदी से बढ़ती आय, खुले रोजगार के अवसर
- आर्थिक उन्नति ने बदली गांवों की तस्वीर

महिलाएं
- स्वास्थ्य एवं सुपोषण को दी प्राथमिकता
- बराबरी के अवसरों ने किया सशक्त

आदिवासी
- अधिग्रहित कृषि भूमि वापस लौटाई
- आदिवासियों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा के लिए गठित समिति

वनाश्रित
- जंगल जमीन पर दिलाये अधिकार
- देश में लघु वनोपजों की सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी

युवा
- युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर
- ई-पंजीकरण के माध्यम से निर्माण कार्यों में अवसर

पर्यावरण
- छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार स्वच्छतम राज्य का खिताब
- प्रतिदिन 1600 टन ठोस कचरे का वैज्ञानिक निपटान
- वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से वन क्षेत्र में इज़ाफा

शिक्षा
- विश्वस्तरीय स्कूलों से नई पीढ़ी को उज्ज्वल भविष्य के समान अवसर
- उच्च शिक्षा के नए गुणवत्तापरक केन्द्रों की स्थापना

स्वास्थ्य सेवाएं
- घर की चौखट तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं
- सभी आय वर्गों को रियायती दरों पर जेनेरिक दवाएं

खेल
- भविष्य के लिए प्रतिभासम्पन्न प्रतिभागियों का निर्माण
- खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व बेहतर प्रशिक्षण

उद्योग
- नई औद्योगिक नीति से समावेशी निवेश के खुले नए द्वार
- आदिवासी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन

बिजली
- लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ
- बिजली से किसानों, वनाश्रितों व उद्योगों की बदल रही तस्वीर

शहरी विकास
- हर घर शुद्ध पेयजल
- मुख्यमंत्री मितान योजना से घर-घर तक पहुंच रहीं नागरिक सेवाएं
- झुग्गी झोपड़ी वासियों को मिला भूमि के स्वामित्व का अधिकार

3 साल
बात है अभिमान के
छत्तीसगढ़िया
स्वाभिमान के

R.O. No. : 11681/12

बात है अभिमान के
छत्तीसगढ़िया
स्वाभिमान के

नई उद्योग नीति की सफलता

छत्तीसगढ़ शासन

- 1751 उद्योग स्थापित
- 19,550 करोड़ रू. निवेश
- 32,912 लोगों को रोजगार

R.O. No. : 11691/2

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

"हमने तय किया है कि हमारे राज्य में उपलब्ध खनिज तथा वन संपदाओं का राज्य में ही मूल्यसंवर्धन हो, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें। विभिन्न प्रयासों से तीन वर्ष के अल्प काल में 1751 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं जिसमें 18 हजार 882 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश किया गया है। 32 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। 149 एमओयू हुए हैं जिनमें 73 हजार 704 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।"

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सेवा, जतन, सरोकार - छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क